



एसआईआर को लेकर दिल्ली-महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने किया बड़ा बदलाव

नयी दिल्ली २६/०९ (संवाददाता): भारत के चुनाव आयोग ने शनिवार को वोटर लिस्ट के चल रहे स्पेशल इंटेन्सिव रिविज़न (स्ट्रक्च) को बेहतर बनाने के लिए कई उपायों की घोषणा की। इनमें नोटिस पाने वाले वोटर्स के लिए घर-घर जाकर वेरिफिकेशन, ऑनलाइन सुनवाई का ज्यादा इस्तेमाल और कमजोर वर्गों के लिए खास मदद शामिल है। आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में दावे और आपत्तियाँ दर्ज करने की समय-सीमा भी बढ़ा दी है, जिससे वोटर्स को अपनी चिंताएँ बताने या लिस्ट में सुधार की मांग करने के लिए ज्यादा समय मिल सके।

ईसीआई ने एक बयान में कहा संशोधित SIR प्रक्रिया के तहत, जिन वोटर्स को नोटिस मिले हैं ज्योंकि उन्हें अनपैड माना गया है या उनमें लॉजिकल कमियां पाई गई हैं। उन्हें आम तौर पर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) या असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन



ऑफिसर (AER O) के सामने पेश होने की जरूरत नहीं होगी। आयोग ने बताया कि यह फैसला 26 सितंबर, 2026 को हुई बैठक के बाद लिया गया और इसे पूरी आयोग ने मंजूरी दी। इसके बजाय, बृथ लेवल ऑफिसर ऐसे वोटरों के घर जाकर जरूरी दस्तावेज इकट्ठा करेंगे और उन्हें श्रद्धा द्वारा विचार किए जाने के लिए ECINET पोर्टल पर अपलोड करेंगे। आयोग ने कहा कि इससे वोटरों को चुनाव कार्यालय जाने

की ज़रूरत कम हो जाएगी।

ईसीआई ने कहा कि सुनवाई सिर्फ शत्रु द्वारा तय किए गए खास मामलों में ही होगी और प्राथमिकता के तौर पर इसे ऑनलाइन किया जाएगा। अगर सुनवाई की जरूरत पड़ती है, तो वोटर के परिवार का कोई बालिग सदस्य वोटर की तरफ से पेश होने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। अधिकारियों को ऑनलाइन सुनवाई के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश भी दिए

गए हैं। इसीआई ने ज़िला चुनाव अधिकारियों से कहा कि वे स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से ज़रूरी हेल्प डेस्क बनाएँ और स्पेशल कैम्प लगाएँ। वे कैम्प नाइट्स स्ट्रैटर्ज में रहने वाले लोगों, मजदूरों, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों, बेघर लोगों और उन अन्य लोगों की मदद के लिए होंगे जिन्हें वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने या सुधार करवाने की प्रक्रिया में मुश्किल हो सकती है। गोवा में उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए श्रद्धु ने कहा

गोवा के मुख्य चुनाव अधिकारी (एथ्रह) ने ब्रह्महृद को निर्देश दिया है कि वे वोटर लिस्ट से छूटे हुए वोटर्स के घर-घर जाकर उनसे फॉर्म भरवाएँ। आयोग के अनुसार, ऐसे 97 वोटर्स में से 81 ने वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने के लिए पहले ही फॉर्म 6 जमा कर दिया है।

स्व्क्र को कंट्रोल करने वाले कानूनी ढांचे पर, कमीशन ने कहा कि इस प्रक्रिया के लिए फॉर्म 6 के साथ जुड़ी घोषणा को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है। कमीशन ने कहा, SIR के दायरे से बाहर की अवधि के लिए, आवेदन %रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960 के तहत प्रोसेस किए जाते रहेंगे।

ईसीआई ने अपने ECINET सिस्टम की समीक्षा करने की भी घोषणा की। उसने कहा कि फोर्ड अधिकारियों को अभी उनके कानूनी अधिकारों के अनुसार प्लेटफॉर्म का रोल-बैस्ड एंजसेस (भूमिका-आधारित पहुंच) मिला हुआ है।

नयी दिल्ली २६/०९
(संवाददाता): भारतीय जनता

पार्टी (भाजपा) ने शनिवार को कहा कि निर्वाचन आयोग के ताजा बयान ने एसआईआर मुद्दे पर कांग्रेस और राहुल गांधी के झूठ और दुष्प्रचार की पोल खोल दी है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे और दुष्प्रचार कर रहे थे। वह एक गंभीर राजनेता नहीं हैं। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को कहा कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) से संबंधित सभी आदेश तीनों चुनाव आयुक्तों की मंजूरी के बाद जारी किए गए थे, और फॉर्म छह में बदलाव को उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा है। फॉर्म 6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दो चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेदों को लेकर जारी विवाद के बीच आयोग ने एक बयान में कहा कि दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी द्वारा कैबिनेट सचिव को भेजे गए पत्र आयोग के किसी



नीतिगत मामले या इसके आईटी विभाग से संबंधित नहीं थे, बल्कि निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर तैनात एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित थे। पूर्ण पीठ की मंजूरी से जारी एक बयान में आयोग ने कहा कि संबंधित अधिकारी द्वारा जारी कार्य-पुनर्वितरण के आदेश दो निर्वाचन आयुक्तों के आदेश के बाद वास्तव में लागू नहीं किए गए थे। साथ ही, उप निर्वाचन आयुक्त (डीईसी) आर से आईटी प्रभाग की निगरानी भी कभी वापस नहीं ली गई थी। इस मामले पर टिप्पणी करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रसाद ने कहा, 'मीडिया में आई तथ्यात्मक रूप से गलत एक खबर के आधार पर विपक्ष, विशेष रूप से राहुल गांधी, निराधार व बेशर्मी भरे

आरोप लगा रहे थे। उन्होंने कहा, निर्वाचन आयोग के बयान ने कांग्रेस और राहुल गांधी की पोल खोल दी है। प्रसाद ने दूसरे विपक्षी दलों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें आयोग पर निराधार आरोप लगाने के बजाय चुनाव जीतने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। यह घटनाक्रम इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के बाद सामने आया, जिसमें दावा किया गया था कि निर्वाचन आयोग को सुखबौर सिंह संधू और वित्तक जीश्री ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार उन फैसलों और आदेशों पर आधिकारिक तौर पर आपर्जित जताई थी, जो उनकी जानकारी के बिना जारी किए गए थे, जबकि एसआइआर का राष्ट्रीय स्तर पर कियान्वयन पूर्ण आयोग की देखरेख में हो रहा था।

चुनाव आयोग के बयान से राहुल गांधी के झूठ की पोल खुली-भाजपा

एसआईआर से ९३ लाख नाम हटाकर भाजपा की मदद का आरोप, ममता बनर्जी ने सीईसी से मांगा इस्तीफा

कोलकाता २६/०९
(संवाददाता) : पश्चिम बंगाल
की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी
ने शनिवार को आरोप लगाया
कि निर्वाचन आयोग (ईसी)
ने मतदाता सूची के विशेष गहन
पुनरीक्षण (एसआईआर) के
जरिये वैध मतदाताओं के नाम
हटाकर राज्य विधानसभा चुनाव
में भाजपा की जीत में मदद
की। उन्होंने राज्य पुलिस पर
मुर्शिदाबाद की अल्पसंख्यक
बहुल रेजिनगर विधानसभा सीट
पर छह अक्टूबर को होने वाले
उपचुनाव से पहले सज़ारूढ़
भाजपा के इशारे पर काम करने
का भी आरोप लगाया। मई में
विधानसभा चुनाव में तृणमूल
कांग्रेस (टीएमसी) की हार के
बाद राज्य की राजधानी
कोलकाता के बाहर अपनी
पहली जनसभा के तहत हुगली
जिले के श्रीरामपुर में एक रैली



को संबोधित करते हुए ममता ऑल इंडिया तुणमूल कांग्रेस की प्रमुख बनर्जी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा और हालिया खबर का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा कि भाजपा ने निर्वाचन आयोग का किस तरह इस्तेमाल किया, इसका सच अब सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि जब तक कुमार इस्तीफा नहीं देते, तब तक देशव्यापी विरोध-प्रदर्शन जारी रहेंगे। मतदाता

सूची से मतदाताओं के नाम व्यवस्थित रूप से हटाए जाने का आरोप लगाते हुए बर्नजी ने मुज्य निर्वाचन आयुक्त के नाम पर तंज कसते हुए कहा, 'वैज्ञानिक (ज्ञानेश) कुमार को जाना ही होगा। जब तक वह इस्तीफा नहीं देते, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान लगभग 93 लाख नाम या तो हटा दिए गए या विचाराधीन रखे गए। बर्नजी ने

आरोप लगाया कि इस कवायद का उद्देश्य राज्य पर कब्जा करने में भाजपा की मदद करना था। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में राज्य पर कब्जा करने के लिए एसआईआई करवाया गया था। 93 लाख नाम या तो हटा दिए गए या उन्हें विचाराधीन रखा गया। पूर्व मुख्यमंत्री ने पुलिस को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि उसका काम लोगों की सुरक्षा करना है, न कि उन्हें राजनीतिक बैठकों में शामिल होने से रोकना। उन्होंने कहा, पुलिस मेरी दुश्मन नहीं है। उसका काम लोगों की रक्षा करना है। लेकिन आज वह ज़्यादा कर रही है? उन्होंने आरोप लगाया कि श्रीरामपुर में टीएमसी समर्थकों को शुरुवार रात उनके घरों से उड़ा लिया गया ताकि उन्हें उनकी (बर्जो) सभा में आने से रोका जा सके।

नयी दिल्ली २६/०९ (संवाददाता): कांग्रेस महासचिव और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड़ा ने मुख्य चुनाव आयुक्त (इश्वर) ज्ञानेश कुमार को लेकर चल रहे विवाद के बीच चुनाव आयोग और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मलप्पुरम में समाचार एजेंसी एनआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि दूधध्दू गठबंधन के सभी नेता इस मुद्दे पर एकमत हैं और उनका मानना है कि जो कुछ हो रहा है, वह गैर-कानूनी है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि अगर चुनाव आयोग कथित तौर पर भाजपा की मदद कर रहा है और उसे बढ़ावा दे रहा है, तो स्वाभाविक है कि भाजपा और उसके नेता आयोग के कदमों को सही ठहराने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं के चुनाव से पहले किए जाने

वाले आत्मविश्वास भरे दावों और जमीन पर लोगों के बीच दिखने वाली स्थिति में अंतर नजर आता है। प्रियंका गांधी के मुताबिक, राहुल गांधी की तत्काल मांग है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि दुष्टद्वय गठबंधन इस मुद्दे पर पूरी तरह स्पष्ट है और गठबंधन के प्रत्येक नेता तथा दल की इस बात पर सहमति है कि जो कुछ हो रहा है, वह गैर-कानूनी है। उन्होंने

यह भी कहा कि जिन लोगों पर ऐसे कदम उठाने के आरोप हैं, उनसे जवाब मांगा जाना चाहिए और उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

प्रियंका गांधी ने चुनाव
आयुक्तों को मिले कानूनी
संरक्षण का मुद्दा भी उठाया।
उन्होंने कहा कि ये सुरक्षा
प्रावधान मौजूदा सरकार द्वारा
लागू किए गए हैं और चुनाव
आयुक्तों को उनके काम से जुड़े
मामलों में संरक्षण देते हैं। उन्होंने
कहा कि अगर कोई व्यक्ति देश

प्रियंका गांधी ने की सीईसी ज्ञानेश कुमार की इस्तीफे की मांग

नयी दिल्ली २६/०९

(संवाददाता): कांग्रेस महासचिव और वायनाडा से सांसद प्रियंका गांधी वाड़ा ने मुख्य चुनाव आयुक्त (श्वशुर) ज्ञानेश कुमार को लेकर चल रहे विवाद के बीच चुनाव आयोग और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मलप्पुरम से समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा कि दृष्टष्टु गठबंधन के सभी नेता इस मुद्दे पर एकमत हैं और उनका मानना है कि जो कुछ हो रहा है, वह गैर-कानूनी है। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि अगर चुनाव आयोग कथित तौर पर भाजपा की मदद कर रहा है और उसे बढ़ावा दे रहा है, तो स्वाभाविक है कि भाजपा और उसके नेता आयोग के कदमों को सही ठहराने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं के चुनाव से पहले किए जाने



वाले आत्मविश्वास भरे दावों और जमीन पर लोगों के बीच दिखने वाली स्थिति में अंतर नजर आता है। प्रियंका गांधी के मुताबिक, राहुल गांधी की तत्काल मांग है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि दुष्ट गठबंधन इस मुद्दे पर पूरी तरह स्पष्ट है और गठबंधन के प्रत्येक नेता तथा दल की इस बात पर सहमति है कि जो कुछ हो रहा है, वह गैर-कानूनी है। उन्होंने



यह भी कहा कि जिन लोगों पर ऐसे कदम उठाने के आरोप हैं, उनसे जवाब मांगा जाना चाहिए और उन्हें ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

प्रियंका गांधी ने चुनाव आयुक्तों को मिले कानूनी संरक्षण का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि ये सुरक्षा प्रावधान मौजूदा सरकार द्वारा लागू किए गए हैं और चुनाव आयुक्तों को उनके काम से जुड़े मामलों में संरक्षण देते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति देश

नेपाल में भारी बारिश के बाद बिहार अलर्ट पर

नयी दिल्ली २६/०९ (संवाददाता): नेपाल से निकलने वाली गंडक नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश होने के मद्देनजर बिहार सरकार ने संवेदनशील जिलों में शनिवार को अपनी तैयारियों में और इजाफा किया। एक सरकारी बयान में यह जानकारी दी गयी है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने आज सुबह एक उच्च स्तरीय बैठक में जिला प्रशासनों को अलर्ट रहने तथा नदियों के जलस्तर, तटबंधों, निचले इलाकों, नदी के किनारे बसे गांवों, पुलों और सड़कों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया। जल संसाधन विभाग के एक बयान में कहा है कि यह अलर्ट गंडक, बागमती और कोसी नदी प्रणालियों से जुड़े जिलों के लिए है। जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है उनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी



चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार, खगड़िया और बेगुसराय शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि राज्य के 15 जिलों में बाढ़ से 50.49 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बयान के अनुसार, सुबह 11 बजे गंडक नदी के वाल्मीकिनगर बैराज से 2,86,800 ज्यूसेक पानी छोड़ा गया। नेपाल में भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, इसलिए संबंधित प्रशासन

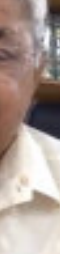
ने इलाके के सभी अधिकारियों को सतर्कता बरतने को कहा है। कोसी नदी का जलस्तर कम हुआ है, लेकिन नदी जिन जिलों से गुजरती है, उन्हें सतर्क रहने को कहा गया है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को नावों, लाइफ जैकेट और बचाव के उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) के दलों को अलर्ट रहने को कहा गया है।

राम मंदिर चढ़ावा मामले पर राजनीति बंद हो-विहिप

२६/०९ (संवाददाता): विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने शनिवार को कहा कि अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी को लेकर पैदा हुआ विवाद अब समाप्त हो जाना चाहिए और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले इसका राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध संगठन ने दावा किया कि उच्चतम न्यायालय की निर्देश पर गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा दाखिल आरोपपत्र में मंदिर निर्माण से जुड़े लोगों या उसके न्यास के सदस्यों की ओर से किसी गड़बड़ी का पता नहीं चला है। विहिप के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने एक वीडियो जारी कर कहा कि चढ़ावे की



गिनती का जिज्मा संभालने वाले कुछ लोगों ने अपराध किया और वे अब जेल में हैं। उन्होंने कहा, “इसके अलावा कोई अन्य अनियमितता नहीं हुई। बाकी हिसाब-किताब भी दुरुस्त है। भगवान राम को अप्रिंत सभी बहुमूल्य वस्तुएं सुरक्षित हैं और उनका उचित हिसाब रखा गया है। न्यासिचित की ओर से किसी गड़बड़ या अपराध का पता नहीं चला है।” विहिप ने कहा



कि जांच के बाद दाखिल करीब 70,000 पत्रों के आरोपपत्र से न्यासियों, न्यास के महासचिव, हिंदू अभियान, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र और मंदिर प्रबंधन को बदनाम करने की सभी “साजिशों” का पर्दाफाश हो गया है। ये दिष्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब मामले की जांच कर रहे उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर गठित एसआईटी ने 23 सितंबर

को अयोध्या की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (भ्रष्टाचार) अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था। आरोपपत्र में कहा गया है कि राम मंदिर के चढ़ावे की रकम में हेराफेरी नकदी की गिनती के दौरान हुई और इसमें ऐसे लोगों का एक समूह शामिल था, जिन्होंने कथित तौर पर रकम निकालकर छिपाई और उसका बंटवारा किया। आरोपपत्र में अभियोजन पक्ष के गवाहों में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्याय के पूर्व महासचिव चंपत राय, न्यासी अनिल मिश्रा और निर्माण प्रभारी गोपाल राव के नाम शामिल हैं।

आरोपपत्र में आठ आरोपियों—अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला उर्फ शनि, लवकुश शुक्ला, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडेय, रमाधेकर मिश्रा, राम शंकर यादव उर्फ टिट्ठू

और सुभाष श्रीवास्तव-के नाम हैं। सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। कुमार ने जांच के निष्कर्षों पर संतोष जताते हुए कहा कि राम मंदिर के लिए एक करोड़ वाले लोगों और न्यास से जुड़े दलस्थियों की ओर से किसी गड़बड़ी का पता नहीं चला है। कुमार ने कहा कि उच्चतम न्यायालय की सिफारिशों के अनुरूप उज्जर प्रदेश सरकार ने एसआईटी का पुनर्गठन कर उसमें एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल किया था और चढ़ावे की कथित चोरी की जांच अब पूरी हो चुकी है तथा इसमें जिम्मेदार लोगों की पहचान कर ली गई है। उन्होंने कहा, “हमें उज्जनी है कि अब इस मुद्दे पर राजनीति बंद होगी। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में राम मंदिर के इस मुद्दे का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।



विविध समाचार



जनता की सेवा और भरोसे से आता है लगातार सज़ा में रहने का विश्वास-नितिन नवीन

नयी दिल्ली २६/०९ (संवाददाता): भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान पर पलटवार करते हुए शुक्रवार को कहा कि भाजपा नेताओं में लगातार सज़ा में बने रहने का विश्वास जनता की सेवा करने और उसका भरोसा जीतने से आता है। नवीन ने यहां दादिया में ‘सेवा संकल्प सभा’ को संबोधित करते हुए कहा कि देश आज ‘विकसित भारत’ के सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने राहुल गांधी के बृहस्पतिवार को किए गए संवाददाता सम्मेलन का जिक्र किया, जिसमें कांग्रेस नेता ने सवाल किया था कि भाजपा नेता यह कैसे कह सकते हैं कि उनकी पार्टी दशकों तक सज़ा में बनी रहेगी। नवीन ने कहा, “नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पूछ रहे थे कि भाजपा की सरकारें लगातार ज्यों आती हैं और भाजपा के नेता ज्यों कहते हैं कि हम अगले 25 साल तक जनता की सेवा करेंगे। मैं उन्हें

बताना चाहता हूँ कि यह विश्वास जनता की सेवा से आता है, जनता का भरोसा जीतने से आता है और जनता के लिए काम करने से आता है।” राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया था कि जहां कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों को सज़ा-विरोधी लहर का सामना करना पड़ता है, वहीं भाजपा के मामले में यह “गायब” हो जाती है। राहुल ने यह भी सवाल किया था कि भाजपा नेता दशकों तक सज़ा में बने रहने का दावा कैसे कर सकते हैं। नवीन ने कहा कि भाजपा का यह विश्वास कल्याणकारी उपायों और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लोगों के जीवन में किए गए बदलावों पर आधारित है। उन्होंने कहा, “जब गरीबों के लिए चार करोड़ से अधिक घर बनाए जाते हैं तो उनकी दुआएं हमें वोट के रूप में मिलती हैं। जब 12 करोड़ गरीब महिलाओं के लिए शौचालय बनाए जाते हैं और वे सज्जमान के साथ जीवन जी पाती हैं, तो उनकी दुआएं हमें वोट



के रूप में मिलती हैं।” नवीन ने कहा कि आज जनता को प्रधानमंत्री आवास योजना, जनधन, आयुष्मान भारत और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा, “यही कारण है कि जनता का भरोसा भाजपा पर है, क्योंकि भाजपा ‘जनसेवा से राष्ट्रसेवा’ के मंत्र पर काम करती है।” भाजपा अध्यक्ष ने कहा, “आज देश विकसित भारत के सपने के साथ आगे बढ़ रहा है। भाजपा का नेतृत्व, कार्यकर्ता और संगठन इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करना है। क्योंकि हमारा ध्येय है-

राष्ट्र प्रथम।” उन्होंने कहा, “हम केवल सज़ा के लिए नहीं हैं। हम केवल सरकार बनाने के लिए नहीं हैं। हम केवल अपनी जीत नहीं देखते। हमारा स्पष्ट ध्येय जनसेवा है।” नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में ‘डबल इंजन’ की सरकार विकास योजनाओं को गांवों और कस्बों तक पहुंचा रही है, जिससे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की भावना धरातल पर साकार हो रही है।

उन्होंने कहा कि अंत्योदय की भावना को जमीन तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका विधायकों, सांसदों तथा निकाय

और पंचायत के प्रतिनिधियों की है, क्योंकि उनका जनता से सीधा जुड़ाव होता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का पिछले 25 वर्षों का सार्वजनिक जीवन जनता की सेवा के लिए समर्पित रहा है, उनसे प्रेरणा लेकर सेवा की भावना से काम करते हुए आमजन के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहिए। उन्होंने जनप्रतिनिधि के रूप में लंबे समय तक काम करने के अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों की कार्यशैली का जनता से सीधा जुड़ाव होना चाहिए। दादिया में ‘सेवा संकल्प सभा’ का आयोजन भारतीय जनसंघ के विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर किया गया था। इसमें हालिया नगर निकाय चुनावों में निर्वाचित भाजपा पार्षद भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पिछले पौने तीन साल के कार्यकाल में प्रदेश में पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवहन के क्षेत्र में

ऐतिहासिक काम हुए हैं।

उन्होंने कहा कि लाखों युवाओं के रोजगार के सपने साकार हुए हैं। शर्मा ने दावा किया कि उनकी सरकार ने संकल्प पत्र के 78 प्रतिशत काम महज ढाई साल के कार्यकाल में पूरे कर लिए हैं। शर्मा ने दावा किया कि कांग्रेस लगातार सिमट रही है क्योंकि लोगों का भरोसा अब भाजपा पर है। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा राज्य में आगामी पंचायती राज चुनावों में भी “ऐतिहासिक जीत” दर्ज करेगी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस अवसर पर राज्यसभा सदस्य नितिन नवीन और मुख्यमंत्री शर्मा ने विभिन्न जिलों के लिए 2,636 करोड़ रुपये की लागत वाली 929 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के 36 लाख लाभार्थियों के खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 400 करोड़ रुपये की राशि हस्तांतरित की गई।

सास-ससुर को गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी बहू की नहीं-हाईकोर्ट

इलाहाबाद २६/०९ (संवाददाता): इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता (बीएन एसएस) की धारा 144 के तहत एक बहू अपने सास-ससुर को गुजारा भत्ता देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह ने कहा कि गुजारा भत्ते के दावे का अधिकार एक सांविधिक अधिकार है जो इस धारा में उल्लिखित व्यक्तियों के वर्गों तक ही सीमित है और सास-ससुर इस प्रावधान के दायरे में नहीं आते। अदालत ने कहा कि हालांकि यह एक नैतिक दायित्व प्रतीत हो सकता है, लेकिन इसे एक कानूनी अनिवार्यता की अनुपस्थिति में एक कानूनी दायित्व के तौर पर लागू नहीं किया जा सकता। बुजुर्ग दंपति राकेश कुमार और उनकी पत्नी द्वारा अपनी बहू के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने चार फरवरी को दिए निर्णय में कहा, “विधायिका ने अपने

विवेक से सास-ससुर को उक्त प्रावधान के दायरे में शामिल नहीं किया है। बुजुर्ग दंपति ने आगरा की परिवार अदालत के प्रधान न्यायाधीश द्वारा अगस्त, 2025 में पारित आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था। निचली अदालत ने भी गुजारा भत्ता की मांग वाले उनके आवेदन को खारिज कर दिया था। बुजुर्ग दंपति की दलील थी कि वे बूढ़े, अनपढ़, दरिद्र और पूरे जीवन अपने मृतक बेटे पर पूरी तरह से निर्भर थे। उज्जर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात उनकी बहू की पर्याप्त आय है और उसने उनके मृतक बेटे के सेवानिवृत्त के लाभ भी प्राप्त किए हैं। उन्होंने कहा कि बूढ़े सास-ससुर का भरण-पोषण करना उनकी बहू का नैतिक दायित्व है और इसे कानूनी दायित्व के तौर पर माना जाना चाहिए। हालांकि, अदालत ने इस आधार पर यह दलील खारिज कर दी कि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है।

कांग्रेस नेता भी जाएंगे सपा के गढ़ इटावा, मैनपुरी और कनौज-अजय राय

लखनऊ २६/०९ (संवाददाता): समाजवादी पार्टी (सपा) प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लोकसभा क्षेत्र रायबरेली के दौरे के एक दिन बाद शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि लोग देश के किसी भी हिस्से में जाने के लिए स्वतंत्र हैं और उनकी पार्टी के नेता भी आने वाले दिनों में सपा के गढ़ - इटावा, कन्नौज और मैनपुरी के दौरे कर सकते हैं। राय ने शुक्रवार को ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, कोई भी देश के किसी भी हिस्से का दौरा करने के लिए स्वतंत्र है। वह (यादव) रायबरेली गए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं था।

हम भी निश्चित रूप से इटावा, कन्नौज और मैनपुरी जाएंगे। बृहस्पतिवार को, समाजवादी पार्टी के प्रमुख यादव अपने विशेष रूप से तैयार किए गए पीडीए रथ पर सवार होकर रायबरेली के दौरे पर निकले थे। अगले साल होने वाले उज्जर प्रदेश चुनावों के अपने अभियान के तहत, यादव राजनीतिक रूप से प्रभावशाली पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक (पीडीए) मतदाताओं से जुड़ने के लिए पीडीए रथ से पूरे राज्य की यात्रा करने वाले हैं। यादव कन्नौज से, उनकी पत्नी डिंपल मैनपुरी से लोकसभा सांसद हैं, जबकि चाचा शिवपाल इटावा के जसवंतनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। सिटीगाइड खोजें



भाजपा ने बृहस्पतिवार को यादव के रायबरेली दौरे पर चुटकी लेते हुए दावा किया था कि यह दौरा उस संसदीय क्षेत्र में सपा की राजनीतिक ताकत दिखाने और वहां कांग्रेस की स्थिति पर सवाल उठाने के लिए किया गया था। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा था, आदर्श रूप से, कांग्रेस को अब अपना राजनीतिक अभियान कन्नौज और मैनपुरी से शुरू करना चाहिए। भाजपा ने यह भी याद दिलाया कि हाल ही में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और सपा सांसद इकरा हसन के बयानों से ऐसा लगता है कि 2027 के उज्जर प्रदेश चुनावों से पहले दोनों विपक्षी दल खुद को बेहतर साबित करने की होड़ में शामिल हैं।

मसूद और हसन ने अपने-अपने नेताओं राहुल गांधी

और अखिलेश यादव को मुख्य विपक्षी चेहरे के रूप में पेश किया था। राय ने शुक्रवार को कहा कि राहुल गांधी देश में विपक्ष की सबसे प्रमुख आवाज हैं। हालांकि, उन्होंने मसूद और हसन के बयानों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और कहा कि पार्टी नेतृत्व गठबंधन व सीट बंटवारे की व्यवस्था पर अंतिम फैसला लेगा।

राय ने कहा, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि राहुल जी ही भाजपा का मुकाबला करने में सक्षम सबसे प्रमुख विपक्षी नेता हैं। रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में आने वाली पांच विधानसभा सीट में से तीन - बछरावां, हरचंदपुर और सेरनी से सपा के विधायक हैं जबकि बाकी दो सीट रायबरेली और ऊंचाहार से भाजपा के विधायक हैं।

नयी दिल्ली २६/०९ (संवाददाता): योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री जैसा बड़ा पद संभालने वाले सुहेलदेव राजभर समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर भी अब मुख्यमंत्री बनने का जवाब देखने लगे हैं। यूपी की सज़ा योगी आदित्यनाथ संभाल रहे हैं और साल 2027 का यूपी चुनाव भी योगी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। यह बात तो सभी जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री बनाने का एक अलग राग छेड़ दिया है। अब चाहे इसके लिए भले ही यूपी जैसे बड़े राज्य के चार टुकड़े हो जाए। मुख्यमंत्री तो राजभर का बेटा ही बनेगा। दरअसल जिस उज्जर प्रदेश का एक हिस्सा काटकर अलग राज्य उज्जराखंड बना दिया गया उस उज्जर प्रदेश को एक बार फिर बांटने की चर्चाएं तेज होने लगी और इस बार सिर्फ एक हिस्से में नहीं यूपी को चार हिस्सों में बांटने की बात हो रही है और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने तो यहां तक ऐलान कर दिया है कि जब भी यूपी का बंटवारा होगा तो पूर्वांचल का मुख्यमंत्री राजभर का बेटा ही होगा। 24 साल से हम लोग इस बात को कहते आए हैं कि जिस दिन प्रदेश का बंटवारा होगा पश्चिम के लोग हरित प्रदेश की बात करते हैं। बुंदेलखंड के लोग बुंदेलखंड



की बात करते हैं। पूर्वांचल के लोग पूर्वांचल की बात करते हैं। इसी उज्जर प्रदेश से उज्जराखंड बना रहा है। बिहार से झारखंड और छत्तीसगढ़ बना है। तो इतना बड़ा प्रदेश है। जब प्रदेश का बंटवारा होगा 5 साल लगे, 10 साल लगे, 20 साल लगे जब भी बंटवारा होगा तो उज्जर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री राजभर का बेटा होगा। ओम प्रकाश राजभर होंगे। अब हम सब तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे? राजभर ने प्रदेश को बांटने में अड़चन का जिक्र करते हुए कहा कि एक सिस्टम है। सिस्टम में चल रहा है अपना काम। हमारी हमारी पार्टी का अपना मानना है। हम अपने जो मेनिफेस्टो है उसमें हम अपने विचार लोगों की राय से पूर्वांचल के लोगों की राय से रखा गया है। जिस सुहेलदेव समाज पार्टी का अस्तित्व ही बीजेपी के दम पर है। उस पार्टी

के अध्यक्ष राजभर यूपी के बंटवारे का सपना देख रहे हैं और यूपी का बंटवारा होते ही पूर्वांचल में राजभर के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर रहे हैं। वह भी ऐसे समय में जब कुछ ही महीनों बाद यूपी में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इस वक्त उन्हें राजभर के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का अभियान छोड़कर 2027 में लगातार तीसरी बार योगी सरकार बनाने पर काम करना चाहिए था। लेकिन यूपी चुनाव से पहले ही वह राजभर के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का अभियान चलाने लगे। जबकि अभी तो यूपी का बंटवारा भी नहीं हुआ है। यही वजह है कि उनके इस बयान पर योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने भी नसीहत देते हुए कहा कि हमें मोदी जी पर भरोसा रखना चाहिए। वह जो भी फैसला लेंगे प्रदेश के हित में लेंगे।

सभी को इस बात को मानना चाहिए और उसी आधार पर अपना बयान भी देना चाहिए। हम सब लोग लगातार 60 और 70 के दशक से यह बात सुन रहे हैं। जनता तो धैर्य के साथ सारे चीज का इंतजार कर रही है। मैं अपने सहयोगी दल के साथियों से भी मैं कहूंगा कि वह भी धैर्य बनाए रखें। आज देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सामर्थ्यवान सरकार चल रही है। देश के हित में जो कुछ भी होगा और प्रदेश के हित में भी जो कुछ होगा वो हम सब लोगों को माननीय मोदी जी के ऊपर छोड़ना चाहिए। भारत के सरकार के ऊपर छोड़ना चाहिए। हम सब लोग यह भी जानते हैं कि किसी भी प्रदेश के बंटवारा करने का अधिकार देश की सरकार के पास है। माननीय मोदी जी के पास है। उनकी सरकार के पास है। तो हम सब

लोगों को भरोसा रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। मोदी जी का जो फैसला है वही प्रदेश के हित में भी है और देश के भी हित में है। सब लोगों को इस बात को मानना चाहिए। उसी आधार पर अपने बयान भी देने चाहिए और आगे भी चलना चाहिए। योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर का यह बयान बता रहा है कि बीजेपी को भी ओम प्रकाश राजभर का यह बयान रास नहीं आया क्योंकि उनका यही बयान अब योगी सरकार को भारी पड़ रहा है। ओम प्रकाश राजभर के बहाने सपा नेता शिवपाल यादव ने तो सरकार पर सवाल उठाते हुए यहां तक कह दिया कि पहले बेईमानी और भ्रष्टाचार खत्म करिए। पूर्वांचल बनेगा तो पश्चिमी उज्जर प्रदेश भी बनेगा। फिर दक्षिण भी दक्षिण भी बनेगा बुंदेलखंड बनेगा। फिर रोहेलखंड बनेगा। बनेगा पहले तो ये ये तो पहले ये तो विचार पहले करो। पूर्वांचल की बात तो तब करो पहले सब एक करो। कितने प्रदेश बनाओ? भाई एक कितने प्रदेश बनाओ? अखिलेश यादव ने भी राजभर के बयान के बहाने योगी सरकार पर पलटवार करते हुए कहा जो देश के बंटवारे की बात कर रहे हैं वह राज्य के बंटवारे की भी बात कर रहे हैं। हमें अपने देश को ताकतवर बनाना है। कमजोर लोग ऐसी बातें करते हैं और कुछ लोग इनके साथ अंडरग्राउंड लेवल पर होंगे।

यौन शोषण के मामले में बृजभूषण शरण सिंह की बढ़ेंगी मुश्किलें? फिर कोर्ट पहुंचीं 4 महिला रेसलर

नयी दिल्ली २६/०९ (संवाददाता): चार महिला पहलवानों ने दिल्ली की एक अदालत में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को यौन उत्पीड़न के मामले में बरी किए जाने को चुनौती दी। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के 3 अगस्त के फैसले को पुराना और रूढ़िवादी धारणाओं पर आधारित बताया। पहलवानों ने सीनियर वकील रेबेका जॉन के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज दिग्विनय सिंह

की अदालत में क्रिमिनल रिविज़न याचिका दायर की है और इस पर शनिवार को सुनवाई होनी है। याचिका में कहा गया है कि बरी करने का फैसला कानून के नज़रिए से टिकने लायक नहीं था और यह कानून के स्थापित सिद्धांतों के बजाय अटकलों और अनुमानों पर आधारित था। याचिका में कहा गया यह फैसला कानून के नज़रिए से टिकने लायक नहीं है और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों की साफ़ तौर पर गलत और चुनिंदा

समझ पर आधारित है। अपील में आगे यह तर्क दिया गया कि विवादित आदेश अटकलों और अनुमानों पर आधारित था और इसमें कानून के बाध्यकारी और स्थापित सिद्धांतों को लागू नहीं किया गया।

इसमें कहा गया है कि जिस आदेश पर सवाल उठाया गया है, उसका मुख्य आधार यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ की शिकायत महिलाओं के अपेक्षित व्यवहार के बारे में पुरानी और रूढ़िवादी धारणाएं



हैं, न कि पीड़ितों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सबूतों पर आधारित निष्पक्ष

प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद सिंह और झुझरु के पूर्व असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया। सिंह को बरी करते हुए अदालत ने कहा कि उन पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप झुझरे और मनगढ़ंत थे, और ये एक गहरी साजिश का हिस्सा थे जो राजनीति से प्रेरित लगती है। एक विस्तृत फैसले में एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अधिनी पंवार ने कहा मुझे यह कहने में कोई

हिचकिचाहट नहीं है कि पीड़ितों का बयान अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से कमजोर करता है और यह भी दिखाता है कि सभी आरोप झूठे और मनगढ़ंत हैं, जो आरोपियों के खिलाफ एक गहरी साजिश के तहत लगाए गए थे और जो राजनीति से प्रेरित लगती है। कोर्ट ने मंगोलिया में ओलंपिक क्वालिफिकेशन के दौरान हुई एक कथित घटना पर सुनवाई की। कोर्ट ने पाया कि शिकायत करने वाले के बयानों में घटना

के समय और जगह को लेकर अहम विरोधाभास थे। कोर्ट ने कहा एक बयान में कहा गया कि घटना 2015 में तुर्की में हुई थी, जबकि बाद के बयान में कहा गया कि वही घटना 2016 में मंगोलिया में हुई थी। अदालत ने कहा यह अंतर केवल मामूली या बाहरी विवरणों में कोई बदलाव नहीं है; बल्कि यह कथित घटना के मूल विवरणों से जुड़ा है, यानी वह देश और वर्ष जिसमें कथित तौर पर यह घटना हुई थी।



झीलों और दलदलों के राजा फ्लेमिंगो

फ्लेमिंगो एक अत्यंत सुंदर और आकर्षक पक्षी है जिसे दुनिया भर में इसकी गुलाबी रंगत और लंबी टांगों के लिए जाना जाता है। यह पक्षी मुख्य रूप से खारे पानी की झीलों, दलदली क्षेत्रों और लैगून में पाया जाता है, जहाँ यह झुंड में रहकर सामूहिक जीवन जीता है। फ्लेमिंगो की छह प्रमुख प्रजातियाँ हैं जिनमें ग्रेटर, लेंसर, चिल्ली, जेम्स, एंजियन और अमेरिकन फ्लेमिंगो शामिल हैं, जो अलग-अलग महाद्वीपों में फैली हुई हैं। इनका गुलाबी रंग उनके विशेष भोजन – जैसे कार्टेथिऑन, प्लवक और शैवाल – में मौजूद बीटा कैरोटीन के कारण होता है। भोजन को छानने के लिए इनकी चौंध विशेष रूप से बनी होती है, जो पानी को छनकर आवश्यक तत्वों को ग्रहण करती है। फ्लेमिंगो का सामाजिक जीवन बेहद सशक्त होता है – ये हजारों की संख्या में एक साथ रहते, उड़ते और प्रजनन करते हैं। प्रजनन काल में नर और मादा मिलकर मिट्टी से एक टीला बनाते हैं और अंडों की देखभाल करते हैं, साथ ही बच्चों को एक खास तरह 'क्रॉप मिलक' पिलाते हैं। भारत में कच्छ का राण और मुंबई की ठाड़ा झील जैसे क्षेत्र इनका प्रमुख आवास स्थल हैं, जहाँ हर साल हजारों फ्लेमिंगो प्रवास के लिए आते हैं। दुर्भाग्यवश, इनका अस्तित्व आज कई चुनौतियों से जुड़ा रहा है – जैसे जल प्रदूषण, प्राकृतिक आवासों का नाश, और मानवीय हस्तक्षेप। इनके संरक्षण हेतु कई अभियारण्य और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनकी सुंदरता के कारण ये फोटोग्राफरों के प्रिय विषय भी हैं, जो प्रकृति प्रेम और जैव विविधता की अहमियत को उजागर करते हैं। इस प्रकार, फ्लेमिंगो न केवल देखने में अद्वितीय है, बल्कि यह हमें प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी का संदेश भी देता है।

फ्लेमिंगो का गुलाबी रंग कैसे आता है?
फ्लेमिंगो का गुलाबी रंग प्राकृतिक रूप से नहीं होता, बल्कि इसका रंग उनके खानपान पर निर्भर करता है। फ्लेमिंगो झीलों और दलदलों में पाए जाने वाले कार्टेथिऑन और शैवाल खाते हैं, जिनमें बीटा कैरोटीन नामक एक रंजक तत्व पाया जाता है। यह तत्व धीरे-धीरे उनके पंखों में गुलाबी रंग पैदा करता है। यही कारण है कि बच्चे स्फेद या भूरे रंग के होते हैं और बड़े होते-होते गुलाबी हो जाते हैं। यह रंग उनकी आहार शैली और पर्यावरण की गुणवत्ता को भी दर्शाता है।



भारत की साइलेंट सिटी आइजोल, जहां है नो हॉर्न का रिवाज

हमारे देश में ट्रैफिक के बढ़ते शोर से लगभग हर शहर प्रभावित है। बढ़ते शोर के कारण लोग सुकून को तरसते हैं लेकिन आज हम आपको भारत के ऐसे शहर के बारे में बता रहे हैं, जहां आपको ट्रैफिक का कोई शोर सुनने को नहीं मिलेगा। भारत के पूर्वोत्तर हिस्से में बसा है मिजोरम, जिसकी राजधानी है अजवाइल। मिजोरम पहुंचकर आपको गाड़ियों के हॉर्न से ज्यादा फिजाओं का संगीत सुनाई देगा। मिजोरम में लोग बेवजह हॉर्न मारना पसंद नहीं करते। भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम की राजधानी अजवाइल एक ऐसी जगह है जहां ट्रैफिक का शोर नहीं सुनाई देता।

मिजो कल्चर और शांति का रिश्ता

मिजो कल्चर कुछ ऐसा है, जिसे शब्दों में बयान करना जरा मुश्किल है। इसका मकसद मेहमाननवाजी, दयालु और स्वार्थ से परे दूसरों की मदद करना है। कम्युनिटी के तौर पर मिजो हमेशा समुदायों के वेलफेयर को आगे रखते हैं, ना कि खुद के। इसलिए मिजोरम के लोग हॉर्न नहीं मारने का पालन इतनी सख्ती से करते हैं।

ट्रैफिक और शांति का संतुलन

अजवाइल में 3.5 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से 1.5 लाख रजिस्टर्ड वाहन अजवाइल के हैं। चूंकि यहां कार काफी ज्यादा हैं और सड़कें सिकरी हैं इसलिए 15 किलोमीटर का रास्ता तय करने में भी कई घंटों का समय लग जाता है। लेकिन बावजूद इसके शहर ने अपनी एक खास इमेज बनाई है। यहां जिदगी की भाग-दौड़ नहीं है।

आइजोल क्यों कहलाती है साइलेंट सिटी...

साइलेंट सिटी का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि यह शहर सुनसान है। यह ऐसी व्यस्त पहाड़ी राजधानी है जहां यातायात नियमों, सार्वजनिक अनुशासन और हॉर्न न बजाने की संस्कृति ने इसे एक अनुभूति पहचान दी है। आमतौर पर राजधानी भीड़भाड़ और शोरगुल वाली होती है, लेकिन आइजोल के मामले में ऐसा नहीं है, यही वजह है कि इसे साइलेंट सिटी नाम दिया गया है।



पुलिस का योगदान

खलाफ़ि, पुलिस भी इस व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करती है, जैसे कि वह तेज आवाज वाली बाइकों को इजाजत नहीं देती, ट्रैफिक जाम में ओवरटेक करने की कोशिश करने वालों को फटकार लगाई जाती है। साथ ही ट्रिस्टर्स को भी इस नियम के बारे में बताया जाता है।



भारत में एक शहर ऐसा भी है जिसे साइलेंट सिटी कहते हैं। वो शहर है मिजोरम का आइजोल। साइलेंट सिटी का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि यह सुनसान शहर है। यह ऐसी व्यस्त राजधानी है जहां ट्रैफिक नियमों का लोग खुद से सख्ती से पालन करते हैं। हॉर्न नहीं बजाते। यहां की भीड़ में कोई शोर नहीं होता।

कितनी ऊंचाई पर है यह शहर...

आइजोल समुद्र तल से लगभग 1,132 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके एक तरफ तलाव नदी घाटी और दूसरी तरफ तुडरियल नदी घाटी है, जो इसकी खूबसूरती में इजाफा करती है। आइजोल की खासियत यह है कि यहां का शांत यातायात सिर्फ एक नारा नहीं है, सालों से, शहर में हॉर्न न बजाने की संस्कृति विकसित हुई है और अब इसे लोकप्रिय रूप से 'नो हॉर्निंग सिटी' के नाम से जाना जाता है।

अपनी बार का इंतजार...

आइजोल में द्वाइवर आमतौर पर हर छोटी-मोटी देर होने पर हॉर्न बजाने के बजाय अपनी बारी का इंतजार करते हैं, हॉर्न बजाना असभ्य माना जाता है और यह सामाजिक आदत शहर की पहचान का हिस्सा बन गई है। इसका नतीजा यह है कि धीमी गति से चलने वाले यातायात में भी शहर शांत महसूस होता है। स्कूली बच्चों, द्वाइवरों और निवासियों को नियमित रूप से सड़क अनुशासन के बारे में याद दिलाया जाता है।

मिजोरम का सांस्कृतिक केंद्र...

आइजोल मिजोरम का राजनीतिक, वाणिज्यिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक केंद्र है। दूसरे भारतीय शहरों के उलट, यहां का शहरी जीवन अयवस्था के बजाय शांति और संयम से चलता है, बढ़ती आबादी और सिकरी पहाड़ी सड़कों के बावजूद, शहर ने अपनी अनुशासित यातायात संस्कृति को बनाए रखा है।

अजवाइल से सीख

- अजवाइल हमें सिखाता है कि शांति और सभ्यता के साथ भी हम सहजता से रह सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है।
- अजवाइल एक ऐसा शहर है जहां शोर नहीं, बल्कि शांति बोलती है। यह शहर हमें सिखाता है कि हम कैसे एक शांत और सौहार्दपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं।



ये है दुनिया की सबसे महंगी मछली, करोड़ों में है कीमत, शिकार करने पर हो सकती है जेल

दुनिया में कई जानवर विलुप्त होने की कगार पर हैं। इसलिए अलग-अलग देशों की सरकारों ने इनके शिकार पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। विलुप्त की कगार पर पहुंच चुके जानवर इतने महंगे मिलते हैं जिनकी कीमत के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आईए जानते हैं एक ऐसी है मछली के बारे में जो दुनिया में सबसे महंगी है। हाल ही में यह मछली इंग्लैंड में दिखाई दी थी। दुनिया में सबसे महंगी बिकने वाली मछली का नाम अटलांटिक ब्लूफिन टूना है। विलुप्त की कगार पर पहुंच चुकी अटलांटिक ब्लूफिन टूना को देखने के बाद हर कोई हैरान है। दुनिया में सबसे महंगी मछली का रिकॉर्ड अटलांटिक ब्लूफिन टूना के नाम है। यह मछली विलुप्त होने की कगार पहुंच चुकी है। इस मछली के संरक्षण के लिए हर साल 2 मई को वर्ल्ड टूना डे मनाया जाता है। इसकी बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2016 में आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड टूना डे मनाने का फैसला लिया था।

ब्रिटेन में सरकार ने अटलांटिक ब्लूफिन टूना के शिकार पर बैन लगा दिया है। इसके अलावा इस मछली को पकड़े पर जेल की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर किसी ने गलती से इसे पकड़ लिया, तो उसे तुरंत समुद्र में छोड़ना होता है। माना जाता है कि इंग्लैंड के कॉर्नवॉल में अटलांटिक ब्लूफिन टूना 100 साल से नहीं देखी गई थी। अब यह मछली में गर्मी के मौसम अवसर दिखाई देती है।



क्या है कीमत

इस मछली से कई रोचक बातें जुड़ी हुई हैं। इस मछली का आकार टूना प्रजाति की मछलियों में सबसे बड़ा होता है और यह बहुत तेज तैरती है। विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी यह मछली पंडुबी से निकलने वाले टॉपीडो हथियार की तरह होती है। इस आकार की वजह से यह समुद्र में लंबी दूरी तक तेज रफतार में तैर सकती है। जानकारों के मुताबिक, इस मछली की लंबाई 3 मीटर तक हो सकती है और वजन करीब 250 किलो होता है। यह मछली इसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। यह दूसरी छोटी मछलियों को खाती है, क्योंकि छोटी मछलियां इसका भोजन होती हैं। अटलांटिक ब्लूफिन टूना मछली का खून गर्म होता है। तैरने वाली मांसेपेशियों में गर्मी अर्जित होने की वजह से यह काफी तेजी से तैरती है। इस मछली की कीमत करीब 23 करोड़ तक हो सकती है।



दुनिया का सबसे बड़ा पौधा, जो ढंक सकता है 28 हजार फुटबॉल के मैदानों को

ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोज निकाला है। ऐसा माना जा रहा है कि इसके एक बीज को मिट्टी में रोपने से यह पौधा फुटबॉल के 28 हजार मैदानों जितने क्षेत्र में फैल सकता है। इस पौधे का नाम 'पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलियस' है।

समुद्री घास प्रजाति का यह पौधा आज से करीब साढ़े 4 हजार वर्ष पुराना है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस पौधे का बीज दो अलग-अलग बास की प्रजातियों के मिश्रण से पैदा हुआ। इतिहास में पहले कभी इस प्रजाति का वर्गीकरण नहीं किया गया। लेकिन, जब ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की तो पाया कि ये दुनिया के किसी भी कोने में पाया जाने वाला सबसे बड़ा पौधा है। ये लगभग 200 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करता है। इसे फाइबर बॉल वीड या रिबन वीड भी कहा जाता

है। आमतौर पर ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी तट पर पाया जाता है। पहले वैज्ञानिकों ने सोचा कि इतने बड़े क्षेत्र में उगने वाले इस पौधे ने कई बीजों से प्रस्यूटित होकर अपना विशालकाय आकार लिया होगा। लेकिन, रिसर्च में पाया गया कि न्यू यॉर्क के

मैनहैटन आइलैंड से 3 गुना क्षेत्र में उगने वाला ये पौधा एक ही बीज से उगा है। ऑस्ट्रेलिया की फ्लिडर्स यूनिवर्सिटी के एक शोधकर्ता ने अपने द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में लिखा कि हम सभी वैज्ञानिक ये जानकार अवचित



कलिंग समाचार



संपादकीय

दलित क्या पानी पीने के हकदार नहीं

देश में धार्मिक और जातीय भेदभाव के कारण समाज में जो दुश्मनी का माहौल बन गया है अब उसमें इसी तरह इतिकाम यानी बदला लेने की घटनाएं हो रही हैं। तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले के वेंगईवयाल गांव में एक झकझोरने वाला मामला सामने आया है। इस गांव के बच्चे पिछले कुछ दिनों से बीमर पड़ रहे थे। डाक्टर ने बीमारी का पता लगाने के लिए पानी की जांच करने कहा। गांव में जिस पानी की टंकी से आपूर्ति होती थीए उस पर चढ़कर देखा गया तो पानी पीला नजर आया। जांच के बाद पता चला कि लगभग 10 हजार लीटर वाली इस पानी टंकी में किसी ने बड़ी मात्रा में मानव मल डाल दियाए ताकि पानी दूषित हो जाए। यह अमानवीय कृत केवल इसलिए हुआए क्योंकि वेंगईवयाल गांव आज भी दलित विरोधी मानसिकता से जकड़ा हुआ है। एक और चिंताजनक और हैरान करने वाली बात ये है कि यह खबर देते हुए कुछ लोगों ने अनुसूचित या दलित समुदाय के लिए बनी पानी टंकी लिखा है। हमने प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं तो पढ़ी हैए लेकिन आजादी के अमृतकाल में भी अगर दलितों की पानी टंकी पढ़ना पड़ेए तो ये समझना कठिन नहीं है कि आजादी का अमृत केवल सवर्ण, संपन्न तबकों के लिए ही है। गरीब पहले भी गुलाम थेए अब भी उनके हालात गुलामों की तरह ही बदतर हैं। जिस गांव में दलितों के पानी पीने पर भी साजिश रची गईए वहां इस बात का भी खुलासा हुआ है कि यहां जातिगत भेदभाव हर जगह है। गांव में चाय की दुकान पर दलितों के लिए अलग गिलास रखे हुए हैं। दलितों का ये भी कहना है कि उन्हें तीन पीढ़ियों से मंदिर के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं है। पानी टंकी को मानव मल से दूषित करने की शिकायत के बाद जब यहां की जिलाधिकारी कविता रामू और पुलिस अधीक्षक वंदिता पांडे गांव में पहुंचीं तब लोगों ने इन सारे भेदभाव की शिकायत की। बताया जा रहा है कि जिस चाय दुकान में दलितों के लिए अलग गिलास रखने का रिवाज थाए उसके मालिक के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलवाने की पहल भी जिलाधिकारी ने की। उन्होंने कहा कि मंदिर के दरवाजे सभी के लिए खुले होने चाहिए और सभी को यहां दर्शन की अनुमति दी जानी चाहिए। भविष्य में ऐसी घटना ना हो इसके लिए यहां कैमरे लगाए जाएं। जिलाधिकारी दलित समुदाय के लोगों को मंदिर के अंदर ले गईं। लेकिन खबरों के मुताबिक जिस समय जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक वहां पहुंचीं तो वहां पर पूजा चल रही थीए उसी दौरान कथित रूप से ऊंची जाति की एक महिला ने अपने शरीर में देवता के आने की बात कही और कहा कि नीची जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर यह बात सही है तो फिर यह समझ लेना चाहिए कि जिलाधिकारी की इस स्वागतयोग्य पहल का कोई भविष्य नहीं है। दरअसल जाति की बेड़ियों ने समाज को इस तरह बांधा हुआ है कि उसे टूटने में सदियां लग जाएंगी। वैसे यह विचारणीय है कि वेंगईवयाल गांव में अगर पानी टंकी का दुखद प्रकरण घटित नहीं होताए तो क्या पुडुकोट्टई जिला प्रशासन को दलितों के साथ हो रहे भेदभाव की खबर लग पाती। अगर तीन पीढ़ियों से दलितों को मंदिर प्रवेश नहीं मिला थाए तो यह बात पहले से प्रशासन के संज्ञान में क्यों नहीं थी। जो भेदभाव जिले के एक गांव में हुआ हैए क्या अन्य गांवों, शहरों का भी वही हाल नहीं होगा। दुखद बात ये है कि दलितों के साथ ये अन्याय उस तमिलनाडु में हुआए जो ई वी रामास्वामी पेरियार की जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों रहें। पेरियार ने पूरी जिंदगी अधविश्वासए अतार्किकताए रूढ़िवादी विचारों और ब्राह्मणवाद की मुखालफत की। उन्हें हिंदू धर्म के खिलाफ बताया जाता हैए लेकिन असल में वे सभी संगठित धर्मों के खिलाफ थे। पेरियार हर तरह के भेदभाव के खिलाफ थेए चाहे वह जाति या धर्म को लेकर हो या फिर लैंगिक आधार पर। इसलिए उन्होंने बाल विवाह के उन्मूलनए विधवा महिलाओं की दोबारा शादी के अधिकारए पार्टनर चुनने या छोड़नेए शादी को इसमें निहित पवित्रता की जगह पार्टनरशिप के रूप में लेनेए आदि के लिए अभियान चलाया था।

भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए नौसेना के विस्तार की आवश्यकता

नन्तु बनर्जी
भारतीय नौसेना की वर्तमान बेड़े की ताकत उत्तर कोरियाए कोलंबियाए मिस्त्रए थाईलैंड और ईरान की तुलना में भी कम है। 2020 तकए भारतीय नौसेना की वास्तविक बेड़े की ताकत की तुलना में पीएलएएन के बेड़े का आकार ,विमान वाहक और पनडुब्बियों सहित 777 युद्धपोतद्ध काफी बड़ा था। अमेरिकी रक्षा विभाग की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएलएएन के कुल बेड़े का आकार ३85 गश्ती लड़ाकों और शिल्प को शामिल नहीं करता है जो एंटी.शिप क़रूज मिसाइल ,एएससीएमद्ध ले जाते हैं। भारतीय नौसेना को मजबूत करने के लिए भारत को आने वाले वर्षों में तेजी से पूंजीगत बजट को बढ़ाना होगाए अपने बेड़े को विस्तारित करना होगाए और आधुनिकीकरण की गति तेज करनी होगी ताकि आकार में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना शक्तिए चीन की पीपुल्स लिबरेशन चीन आर्मी नेवी ,पीएलएएनद्ध से हिंद महासागर तथा प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते खतरों के लिए अकेले जहाजों और उपकरणों के लिए बजट आबंटन 35ए452 करोड़ रुपये था। कुल पूंजी परिव्यय का 75 प्रतिशत इसके बेड़े के लिए निर्धारित किया गया हैए जिसमें युद्धपोतए पनडुब्बी और अन्य उपकरण शामिल हैं। देश के नौसैनिक बल को 2023.24 और उसके बाद भी इसी तरह के बजट की जरूरत है। भारतीय नौसेना को इस क्षेत्र में बढ़ते हुए पीएलएएन के खतरे का सामना करने के लिए अपनी क्षमता को मजबूती से बढ़ाने की आवश्यकता हैए विशेष रूप से भारत के तीन महासागर साझा करने वाले पड़ोसियों- बांग्लादेशए श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ उसके बढ़ते सैन्य गठबंधन के संदर्भ में। दुर्भाग्य सेए भारतीय नौसेना को वह प्राथमिकता नहीं मिलीए जिसकी वह पहले के वर्षों में सरकार से हकदार थी। भारतीय नौसेना की वर्तमान बेड़े की ताकत उत्तर कोरियाए कोलंबियाए मिस्त्रए थाईलैंड और ईरान की तुलना में भी कम है।

का मुकाबला किया जा सके। 2020 तकए भारतीय
सरकार को इस तथ्य को नौसेना की वास्तविक बेड़े की
स्वीकार करना चाहिए कि ताकत की तुलना में पीएलएएन
पीएलएएन भारतीय नौसेना से के बेड़े का आकार विमान
चार गुना बड़ा और मजबूत है। वाहक और पनडुब्बियों सहित
यह सच है कि इस वित्तीय वर्ष 777 युद्धपोतद्ध काफी बड़ा था
में पहली बार भारतीय नौसेना अमेरिकी रक्षा विभाग की एक
का पूंजीगत व्यय लक्ष्य 45 रिपोर्ट में कहा गया है कि
प्रतिशत तक बढ़ाया गया है पीएलएएन के कुल बेड़े का
परन्तु आगे भी इसे बढ़ाने की आकार 85 गश्ती लड़ाकों और
आवश्यकता है। शिल्प को शामिल नहीं करता

पिछले साल के 21000 है जो एंटी.शिप वरूज मिसाइल
करोड़ की तुलना में 2022.23 ;एएससीएमद्ध ले जाते हैं।

के लिए अकेले जहाजों और उपकरणों के लिए बजट आबंटन 35ए452 करोड़ रुपये था। कुल पूंजी परिव्यय का 75 प्रतिशत इसके बेड़े के लिए निर्धारित किया गया है जिसमें युद्धपोत पनडुब्बी और अन्य उपकरण शामिल हैं। देश के नौसैनिक बल को 2023.24 और उसके बाद भी इसी तरह के बजट की जरूरत है। भारतीय नौसेना को इस क्षेत्र में बढ़ते पीएलएएन के खतरे का सामना करने के लिए अपनी क्षमता को मजबूती से बढ़ाने की आवश्यकता है विशेष रूप से भारत के तीन महासागर साझा करने वाले पड़ोसियों- बांग्लादेश श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ उसके बढ़ते सैन्य गठबंधन के संदर्भ में।

दुर्भाग्य से भारतीय नौसेना को वह प्राथमिकता नहीं मिलीए जिसकी वह पहले के वर्षों में सरकार से हकदार थी। भारतीय नौसेना की वर्तमान बेड़े की ताकत उत्तर कोरियाए

आने वाले वित्तीय वर्षों में भारतीय नौसेना के लिए एक ब पर बजट आबंटन मौजूद जहाजों और पनडुब्बियों को आधुनिक बनाने में मदद करेगा और इसके बेड़े के आकार को भी बढ़ायेगा क्योंकि चीन अपनी नौसैनिक पहुंच को और बढ़ा देगा। अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी अत्याधुनिक नौसैनिक शक्तियों के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी- चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, क्राइड के सभी सदस्य, बहुत कम मूल्य की होगी यदि भारतीय नौसेना स्वयं पर्याप्त मजबूत नहीं है हालांकि अमेरिकी बेड़े का आकार 490 जहाज डू चीन की तुलना में छोटा है यह वातक शक्ति में पीएलएएन की तुलना में काफी मजबूत है। वास्तव में अमेरिकी नौसेनाए मारक क्षमता के मामले में ए विमान वाहक और पनडुब्बियों को बेजोड़ ताकत के साथ सबसे आधुनिक और बहुमुखी मानी जाती है।

कोलंबियाए मिस्पए थाईलैंड वलर्ड डायरेक्टरी ऑफ़
ऑर ईरान की तुलना में भी
कम है।
2020 तकए भारतीय
नौसेना की वास्तविक बेड़े की
ताकत की तुलना में पीएलएएन
के बेड़े का आकार विमान
वाहक और पनडुब्बियों सहित
777 युद्धपोतद्ध काफी बड़ा था।
अमेरिकी रक्षा विभाग की एक
रिपोर्ट में कहा गया है कि
पीएलएएन के कुल बेड़े का
आकार 85 गरती लड़ाकों और
शिप्ल को शामिल नहीं करता
है जो एंटी.शिप क्लरूज मिसाइल
एएससीएमद्ध ले जाते हैं ए
वलर्ड डायरेक्टरी ऑफ़
मॉडर्न वारशिप्स 2023
अमेरिकी नौसेना को दुनिया की
सबसे मजबूत नौसैनिक शक्त
मानती हैए इसके बाव
पीएलएएन, रूसी नौसेना,
इंडोनेशियाई नौसेना, कोरिया
गणराज्य की नौसेना, जापान
समुद्री आत्मरक्षा बल और
भारतीय नौसेना का स्थान है।
अमेरिकी नौसेना के पास 11
विमान वाहक 10 हेलीकॉप्टर
वाहकए 68 पनडुब्बी और 92
विध्वंसक हैं। केवल पीएलएएन
के पास अधिक पनडुब्बियां
79द्ध हैं।

आने वाले वित्तीय वर्षों में भारतीय नौसेना के लिए एक ब पर बजट आबंटन मौजूदा जहाजों और पनडुब्बियों को आधुनिक बनाने में मदद करेगा और इसके बेड़े के आकार को भी बढ़ायेगा क्योंकि चीन अपनी नौसैनिक पहुंच को और बढ़ा रहे हैं। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसी अत्याधुनिक नौसैनिक शक्तियों के साथ

रूस में 64 पनडुब्बियां हैं। चीन के 50 और रूस के 15 के मुकाबले अमेरिका के पास 92 विध्वंसक हैं। हालांकि ये अनुमान हमेशा अन्य वैश्विक श्रेणियों के लिए रिपोर्ट से मेल नहीं खाते। इसके अलावा ए एसबस बड़े शौनिक बलों का मतलब एसबस शक्तिशाली बलों से नहीं है।

भारत की बढ़ती भागीदारी-
चतुर्भुज सुरक्षा संवाद; क्राइड
के सभी सदस्य, बहुत कम मूल्य
की होगी यदि भारतीय नौसेना
स्वयं पर्याप्त मजबूत नहीं है।
हालांकि अमेरिकी बेड़े का
आकार 490 जहाज, चीन की
तुलना में छोटा है। यह बातक
शक्ति में पीएलएएन की तुलना
में काफी मजबूत है। वास्तव
में ए अमेरिकी नौसेनाएं मारक
क्षमता के मामले में ए विमान
वाहक और पनडुब्बियों की
बेजोड़ ताकत के साथ सबसे
आधुनिक और बहुमुखी मानी
जाती है।

वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ
मॉडर्न वारशिप्स 2023
अमेरिकी नौसेना को दुनिया की
सबसे मजबूत नौसैनिक शक्ति
मानती है। इसके बाद
पीएलएएन, रूसी नौसेना,

विभिन्न श्रौंसेना निगरानी
एजेंसियां इस बारे में विपरीत
दिशानिर्देश देती हैं कि वे किस
प्रकार के जहाज को किसी देश
की नौसेना का हिस्सा मानते
हैं। उदाहरण के लिए चीन
की नौसेना में इससे 100 से
अधिक होवरक्राट शामिल हैं।
जिन्हें नौसैनिक जहाज माना भी
जा सकता है और नहीं भी।
आधुनिक नौसैनिक बल अक्सर
न केवल सक्रिय ड्यूटी पर
कमीशन किये गये जहाजों को
शामिल करते हैं। बल्कि
गैर-कमीशन वाले जहाजों
सहायक जहाजों ए आरक्षित बेड़े
और यहां तक कि निर्माणाधीन
जहाजों को भी शामिल करते
हैं। ऐसी गणनाओं में हो सकता
है कि किसी देश की नौसेना
जहाजों की सं या पर प्रभाव
का अनुमान है।

इंडोनेशियाई नौसेना, कोरिया आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार भारतीय नौसेना के गणराज्य की नौसेना, जापान के पास 150 युद्धपोत और समुद्री आत्मरक्षा बल और पनडुब्बियाँ चार ईंधन टैंकरों भारतीय नौसेना का स्थान है। एक जवाबी पोतए 24 जलपोतए पनडुब्बीरोधी युद्धक जलपोतए पनडुब्बीरोधी युद्धक उथले जल जहाज, 17 हमलावर पनडुब्बियाँ एक बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बीए 14 फ्रिगेट, 10 विध्वंसक, तथा 799 डू हैं।

रूस में 64 पनडुब्बियाँ हैं। चीन के 50 और रूस के 15 के मुकाबले अमेरिका के पास 92 विध्वंसक हैं।

हालांकि ये अनुमान हमेशा अन्य वैश्विक श्नेवल वॉचश रिपोर्ट से मेल नहीं खाते। इसके अलावाए श्शबसे बड़े श नौसैनिक बलों का मतलब श्शबसे शक्तिशाली श् बलों से नहीं है।

विभिन्न शनौसेना निगरानीश
एजेंसियां इस बारे में विपरीतत
दिशानिर्देश देती हैं कि वे किसस
प्रकार के जहाज को किसी देश
की नौसेना का हिस्सा मानते

हैं। उदाहरण के लिए चीन की नौसेना में इससे 100 से अधिक होवरक्राट शामिल हैं। जिन्हें नौसैनिक जहाज माना जा सकता है और नहीं भी। आधुनिक नौसैनिक बल अक्सर न केवल सक्रिय ड्यूटी पर कमीशन किये गये जहाजों को शामिल करते हैं बल्कि गैर-कमीशन वाले जहाजों पर सहायक जहाजों पर आरक्षित बेड़े और यहां तक कि निर्माणधीन जहाजों को भी शामिल करते हैं। ऐसी गणनाओं में हो सकता है किसी देश की नौसेना के जहाजों की सं या पर प्रभाव का अनुमान है।

आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार भारतीय नौसेना के पास 150 युद्धपोत और पनडुब्बियाँ चार इंधन टैंकरएक जवाबी पोतए 24 जलपोतए पनडुब्बीरोधी युद्धक उथले जल जहाज, 17 हमलावर पनडुब्बियाँ एक बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बीए 14 फ्रिगेट, 10 विध्वंसक, तथा

300 विमान हैं। आठ लैंडिंग शिप टैंक एक उभयचर परिवहन डॉक एक दो विमान वाहक एक विभिन्न छोटी पेट्रोल नौकाएं पूरक जहाज भी हैं। भारतीय नौसेना के पास लगभग 75000 रिजर्व और 67000 से अधिक सक्रिय कर्मी हैं। इसके पास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक पश्चिम बंगाल ए आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, केरल, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र गोवा एक कर्नाटक और गुजरात में पूरी तरह से सुसज्जित और प्रशिक्षण आधार हैं।

संयोजन के कारण अमेरिका प्रमुख वैश्विक नौसैनिक शक्ति बना रहेगा।

अमेरिकी नौसेना के पास न केवल बहुत से जहाज हैं एक बल्कि इसके पास कई विशाल अत्याधुनिक जहाज भी हैं। यूके के जहाजों की कुल सं या में कमी आने की उ मीद है। दो नौ से विमान वाहकों को जोड़ने और इसके पनडुब्बी बेड़े में वृद्धि से ब्रिटेन को नंबर 2 समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित होना चाहिए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अपनी नौसैनिक

इन आधारों से गोला.बारूद समर्थनए रसद और रखरखाव सहायताए समुद्री कमांडो आधारए वायु स्टेशनए आगे संचालन आधारए पनडुब्बी और मिसाइल नाव आधारए मिसाइल रक्षा और तटीय रक्षा प्रदान करने वाले हैं। भारत को नौसेना जल्द ही एक मजबूत वैश्विक नौसैनिक शक्ति बनने की आकांक्षा रखती है।

नेशनल इन्स्टीट्यूट ऑफ़ पर सैन्य विश्लेषकों की 2021 की एक रिपोर्ट में 2030 में दुनिया की पांच शीर्ष नौसेनाओं का अनुमान लगाया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इसने भारतीय नौसेना को रूस से आगे चौथे स्थान पर रखा। यह रिपोर्ट अगले आठ वर्षों में भारतीय नौसेना के विस्तार के बारे में अति-आशावादी है। अमेरिकी नौसेना नंबर 1 हैए उसके बाद ब्रिटिश नौसेना और चीनी नौसेना है। विश्लेषकों को उ मीद है कि टन भार और तकनीकी प्रगति के बेजोड़ जलपोत, पारंपरिक और परमाणु संचालित पनडुब्बियां शामिल हैं। योजना 2050 तक 200 युद्धपोतों और 500 विमानों की एक मजबूत नौसेना बनाने की है। चीन की आक्रामक मुद्रा और भारत.प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए समय सीमा काफी लंबी प्रतीत होती है। सरकार को वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक बने रहने के लिए अपने विस्तार कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए भारतीय नौसेना को वार्षिक पूंजीगत व्यय निधि सहायता जारी रखनी चाहिए।

संयोजन के कारण अमेरिका प्रमुख वैश्विक नौसैनिक शक्ति बना रहेगा।

अमरीकी नौसेना के पास न केवल बहुत से जहाज हैं बल्कि इसके पास कई विशाल अत्याधुनिक जहाज भी हैं। यूके के जहाजों की कुल संख्या में कमी आने की उमीद है। दो नये विमान वाहकों को जोड़ने और इसके पनडुब्बी बेड़े में वृद्धि से ब्रिटेन को नंबर 2 समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित होना चाहिए।

रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अपनी नौसैनिक उपस्थिति का विस्तार कर रहा है और उसके पास 2030 तक तीन ऑपरेटिंग विमान वाहक होने चाहिए जो सामूहिक रूप से 110.120 विमानों को तैनात करने में सक्षम हों। आधिकारिक रिपोर्टों से पता चलता है कि भारतीय नौसेना के पास विभिन्न प्रकार के 45 पोत निर्माणाधीन हैं।

इनमें विध्वंसक, फ्रिगेट, जलपोत, पारंपरिक और परमाणु संचालित पनडुब्बियाँ शामिल हैं। योजना 2050 तक 200 युद्धपोतों और 500 विमानों की एक मजबूत नौसेना बनाने की है। चीन की आक्रामक मुद्रा और भारत प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते तनाव को देखते हुए समय सीमा काफी लंबी प्रतीत होती है। सरकार को वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिक बने रहने के लिए अपने विस्तार कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए भारतीय नौसेना को वार्षिक पूंजीगत व्यय निधि सहायता जारी रखनी चाहिए।

तू नया है तो दिखा सुबह नई शाम नई

वर्षा भूभाणी मिर्जा

इस हिंसा को उकसाते हुए सभी लड़कियों के साथ लड़कों की भी सुरक्षा भूल रहे हैं या इन अपराधों से आंखें मूंदे हुए हैं। बलात्कार के चालीस पीसदी केस वास्तव में बलात्कार के नहीं होते। ये वे मामले हैं जिनमें परिवार उन पुरुषों को बलात्कार के इशारे में मुकदमे दायर करता है जिनसे परिवार की बेटियाँ या तो शादी कर चुकी होती हैं या करना चाहती हैं। परिवार हर कीमत पर इन शादियों को निरस्त कर लड़की को बरामद करना चाहते हैं। क्या यह महज संयोग है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी दो स्त्रियाँ जिनमें एक सांसद और दूसरी मंत्री हैं एक ही समय में कहती हैं कि श्वात्मरक्षा के लिए हथियार रखो और अपने घर में रखें सब्जी तेजने वाले चाकू की धार इतनी तेज करा जो ताकि वक्त आने पर दुश्मन के सर काट सकोश्च इसके लिए करने हैं ये हथियार धारदारष् क्या किसी भी बंदूक की गोली या हथियार पर लिखा होता है कि वह किसकी जान लेगीष् क्या यह तय है कि ये हथियार चुन.चुनकर निशाना साधेंगे और समाज में हिंसा के बाद फिर संस्कार पर लौट आणाष् क्या ऐसे संस्कारित होंगी देश की लड़कियाँ जिनकी बात सांसद महोदया करती हैंष् आखिर क्यों जिं दमदार पदों पर बैठे इन लोगों को संसदए सरकार और देश की व्यवस्था से कोई उ मीद नहीं है जो ये भीड़ को उकसा.उकसाकर हिंसक हो जाने के लिए कह रहे हैंष्

देश के कानून में ऐसी नफ़रती और घृणा फैलाने वाली भाषा के लिए कोई जगह नहीं

हैं। लेकिन फिर भी शासन, प्रशासन सब मूक बने हुए हैं और जो कोई एम्पाइड आ कराना भी चाहता है तो क्षेत्र का एसपी कहता है कि आपको यथाने आना पड़ेगा। यानी सबकी कोशिश है कि ऐसी घृणित बयानबाजी करने वालों को पूरा संरक्षण देना है। कवच प्रदान करना है। क्या यह संरक्षण तब भी मिलेगा जब संसद किसी अलग दल और अलग पार्टी का होशू शायद नहीं। ऐसे वक्त में तमाम व्यवस्था सही दिशा में काम करने लगती है। अपने लिए मनुकानी और दूसरों के लिए कानूनी। क्या ऐसे ही दृश्य का साक्षी नहीं हो रहा है देश इन दिनों? भोपाल का सांघ प्रजा ठाकुर कर्नाटक के शिमोगा में और मध्यप्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर भोपाल में कहा जाती हैं कि श्वात्मरक्षा के लिए हथियार रखो।

सिलसिला चल पड़ा है और अब मध्यप्रदेश के एक और भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी यही घोषणा बुलंद कर दी है। प्रजा ठाकुर तो पहले ही अपने बयानों से प्रधानमंत्री मोदी को दुखी कर चुकी हैं। प्रजा पहले महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता चुकी हैं। तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि शबले ही नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने की बात पर प्रजा माफी मांग चुकी हो लेकिन मैं उन्हें कभी हृदय से क्षमा नहीं कर पाऊंगा। ए० अ० चला हैं फिर दुख बढ़ाती ही चली जा रही है। मुंबई बम विस्फोट में शहीद महाराष्ट्र के एटीएस चीफ हेमंत करकरे के लिए प्रजा कहती हैं, श्वे अपने शाप की वजह से हमारे ए० करकरे चाहते तो मुंबई

पर आतंकी हमले के वक्त नीचे आर्डर पास कर सकते थे लेकिन उन्होंने मोर्चा खुद संभाला।

अपेक्षाकृत कमजोर बुलेटरफ़ैम हेलमेट जो उनका नहीं था और रायफल के साथ मैदान में कूद पड़े। सीने पर गोलीयां खाईं। ये तथ्य उस समय की तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में हैं। वही हेमंत करके मालेगांव बम विस्फोट कांड की भी ठाकुर रहे थे जिसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक आरोपी थीं। सवाल यही है कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुख्या विरोध करने वाली पार्टी यहाँ जान की बाजी लगा देने वालों के लिए पूर्वाग्रही कैसे हो जाती है और फिर यह कैसा दर्द है जो उन्होंने प्रज्ञा को 2019 में भोपाल से लोकसभा का टिकट दिलवा देता हैए उन्हें सांसद बना देता है। आप कहेंगे कि सांसद तो जनता ने बनाया। उसने जितायिए बेशक जनता जो वोट देती हैए जि मंदा है यहाँ इस क्रोनोलाजी पर भी निगाह डालने की जरूरत है कि गुजरात में जो बिलकिस बानो दंगों के दौरान बलात्कार और परिजनों की हत्या का शिकार होती हैं उनके सजाया ता अपराधी रिहा कर दिए जाते हैं और जो सांसद कहती हैं कि अपनी बेटियों को सुरक्षित रखोए अपनी बेटियों को संस्कारित करोए अपने घर में हथियार रखोए कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू ज़रा तेज रखो! स्पष्ट बोल रहा हूँ कि हमारे घरों में भी सब्जी काटने के लिए जो चाकू है उसे तेज रखो। जो सब्जी अच्छे से कटेगी तो दुश्मनों के सर भी अच्छे से कटेंगे।

उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं

को चाकू से गोदा हैण्ण (शरीर) से आम हिंसा के लिए उकसाने वाले इस वक्तव्य में एक और बात अन्तर्निहित है कि आप लड़कियां कभी अपने मन को करें तो उन्हें रोकने में आप हिंसा करने में ज़रा भी संकोच ना करें। इस तरह के धारदार चाकू दुश्मनों पर कितने चल रहे हैं उसका तो आंकड़ा फ़िल्हाल नहीं है लेकिन प्रेम करने वाली लड़कियां मारी जा रही हैं एक काटी जा रही हैं और इतने संताप में हैं कि खुदकुशी भी कर रही हैं। हालांती में एक अभिनेत्री की आत्महत्या को वजह उसका वही रिश्ता था जिसमें श्रद्धा और आपत्ता के प्रकरण का डर बैठने के बाद उनके रिश्ते में तनाव आ गया था। ऐसे उकसाने वाले भाषणों से परिवार और समाज में लड़कियों का जीना मुश्किल हो रहा है।

ऑर कलिंग के नाम पर परिवार अपने बच्चों के साथ हिंसा से भी नहीं चूक रहे व्यवस्था न केवल चुप रहकर सब देख रही है बल्कि बीच-बीच में ताली भी पीट देती है। हस्तक किसी के दर्द में डोल बजाने से भी बुरी मालूम होती है। बाईस साल की निरूपमा पत्रकार थी और प्रियभान्यु रंजन नाम के हमपेशा लड़के को हमसफ़र बनाना चाहती थी। लड़की ब्राह्मण और लड़का कायस्था दोनों दिल्ली में थे। छोटे-से शहरों से झोला उठाकर चलने वाले लड़के, लड़कों में माता-पिता तमाम वाब भर देते हैं लेकिन उसका अहम हिस्सा अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। ख़ूब पढ़ाए-अच्छा जाँव चुनोए ज्यादा कमाओ लेकिन जीवनसाथीघर वह मत चुनो। बेटी को खुला आसमान देने वाले पढ़े-लिखे

अभिभावक भी यहां पहुंचकर उनके पंख कतरना चाहते हैं।

झुमरीतलैयाए बिहार की निरुपमा
के साथ भी यही हुआ।

पुलिस ने परिजनों को गिर तार करते हुए आरोप लगाया कि उसने खुदकुशी नहीं कीए उसकी गला दबाकर हत्या की गयी थी। वह दस ह ते के गर्भ से थी। दर असलए हर मध्यमवर्गीय भारतीय परिवार बच्चों की शादी के जरिये यह साबित करते हैं कि हमारे बच्चों पर हमारी कितनी नकेल है। अपने बच्चों को जी.जान से पालने वाले आखिर इतने कटु और स त बयों हो जाते हैं? इसलिए क्योंकि नेता और इनकी व्यवस्था इन बच्चों की रक्षा करने का आश्वासन नहीं देती? सब जानते हैं कि विशेष विवाह अधिनियम कमजोर किया जा रहा है।

इस हिंसा को उकसाते हुए सभी लड़कियों के साथ लड़कों की भी सुरक्षा भूल रहे हैं या इन अपराधों से आंखें मूंदे हुए हैं। बलात्कार के चालीस पीसदों के बड़े वास्तव में बलात्कार के नहीं होते। ये वे मामलों हैं जिनमें परिवार उन पुरुषों को बलात्कार के इल्ज़ाम में मुकदमे दायर करता है जिनसे परिवार की बेटियां या तो शादी कर चुकी होती हैं या करना चाहती हैं। परिवार हर कीमत पर इन शादियों को निरस्त कर लड़की को बरामद करना चाहते हैं और लड़कों को सलाखों के पीछे डालना चाहते हैं। ये लड़कियां कभी घरों में कैद कर दी जाती हैं तो कभी नौकरी निकेतनों में। यह सोच ही बहुत बकवासों है कि लड़कियां सुरक्षित हो जाएंगी। वह परिवार जिसका बेटा महज प्रेम करने के जुर्म में बलात्कार या अपहरण

की सज़ा भुगत रहा होगा क्या
वह चैन से जी सकता है

भीड़ को उकसाने वाले
इसका जवाब देंगे कैसा अकेला
और डरा हुआ समाज होगा वह
जहां प्रेम और सद्भाव का पूर्ण
तरह अभाव होगा और हर बेटी
के मां.बाप केवल चाकू की धार
तेज करने में ही लगे होंगे। जिन
विचाराधीन कैदियों से भारत की
जेलेन भरी पड़ी हैं उनमें बड़ी
सं या में ऐसे लड़के हैं और
बाहर घुटन में जीती हैं
लड़कियाँ समझौते का जीवन
गुज़ारती हुई। जात.बिरादरी से
दुखी और नफ़रत ने समूचे समाज
के सद्भाव में गहरा घाव कर
दिया है और ये नेता जब.तब
इस घाव को कुरेदते रहते हैं।

है।
 राजनीतिक दल ने घृणा की यह भाषा महिला नेताओं के हिस्से में डाल दी है वह भी निर्वाचित नेता के। क्या यह भी सोचा समझा हुआ है कि सद्भावना और प्रेम में यकीन रखने वाली स्त्री के मुख से ऐसी कड़ु बातें कहलवाई जाएं। भारत की सबसे बड़ी और लोकप्रिय पार्टी को आखिर क्यों इन हिंसक भाषणों का सहारा लेना चाहिए? क्या उसे अपनी लोकप्रियता पर शक है या उसकी इस लोकप्रियता का आधार कमजोर है? जब सत्ता इस कदर असुरक्षित रहेगी तो नागरिक को उसके सुरक्षित रखने का आश्वासन राज्य की ओर से कैसे दिया जा सकता है? क्या जनता नए साल में अपने लिए कुछ बेहतर और नए की उमीद कर सकती। पैसा लुधियानवी का शेर है।

तू नया है तो दिखा सुबह
नईए शाम नईए
वरना इन आंखों ने देखे हैं
नए साल कई॥



किसान और महिलाएं छत्तीसगढ़ के आर्थिक एवं सामाजिक जनजीवन के महत्वपूर्ण आधार-साय ंशासकीय योजनाओं से किसान और महिलाओं का भी हो रहा चहुंमुखी विकास

जशपुरनगर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जशपुर जिले के ग्राम पंचायत नारायणपुर में आयोजित किसान महतारी सज्मेनल में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने प्रदेश के किसान एवं महिलाओं को नमन करते हुए उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सज्मानित किया। साथ ही नारायणपुर सहित आसपास क्षेत्र के लोगों की सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा भी की। इसमें नारायणपुर खेल मैदान में स्टेडियम और ज़लड लाइट, नगर वन शिव मंदिर में मंगल भवन, नारायणपुर अटल चौक से औघड़ा आश्रम तक सोलर लाइट, नारायणपुर में पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास निर्माण एवं काराखेड़का में छठ घाट निर्माण की घोषणा शामिल है। इस अवसर पर विजयमंत्री ओ पी चौधरी, विधायक गोमती साय और रायमुनी भगत, प जागेश्वर यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, नगर पालिका अध्यक्ष जशपुर अरविंद भगत, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह

जूदेव, नगर पालिका जशपुर उपाध्यक्ष यश प्रताप सिंह जूदेव, कृष्ण कुमार राय, विजय आदित्य प्रताप सिंह जूदेव, जिला पंचायत सदस्य अनिता सिंह, दुलारी सिंह एवं मलिता बाई , जनपद पंचायत अध्यक्ष दुलदुला राजकुमार सिंह, सुनील गुप्ता, मुकेश शर्मा, मनीष अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशिमोहन सिंह, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार सहित जनप्रतिनिधिगण और अधिकारीगण मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि किसान और महिलाएं छत्तीसगढ़ के आर्थिक एवं सामाजिक जनजीवन के प्रमुख आधार हैं।

केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विभिन्न वर्गों सहित किसान एवं महिलाओं का भी चहुंमुखी विकास हो रहा है। प्रदेश के किसान प्रधानमंत्री किसान सज्मान निधि, धान खरीदी योजना सहित विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। इसी प्रकार प्रदेश की विवाहित महिलाओं को महतारी

वंदन योजना के माध्यम से प्रतिमाह 1 हजार रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। 21 माह से यह राशि दी जा रही है, यह आगे भी जारी रहेगी। महतारी वंदन योजना से अकेले जशपुर जिले में 2 लाख 29 हजार माताएं-बहनें लाभान्वित हो रहीं हैं। इन्हें अब तक 427 करोड़ रुपये से अधिक राशि का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में धान खरीदी जोर शोर से जारी है। सभी पंजीकृत किसानों से सहकारी समितियों के माध्यम से धान खरीदी की जा रही है। इसके लिए सभी केंद्रों में पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल की मान से धान की खरीदी की जा रही है। साथ ही किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान का दाम मिल रहा है। प्रदेश के करीब 26 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सज्मान निधि का लाभ मिल रहा है। जशपुर जिले के करीब 72 हजार किसानों को हर साल 6 हजार रुपये सज्मान निधि दी जा रही है। जशपुर जिला संभावनाओं का गढ़ बनता जा रहा है। जशपुर की जलवायु ऐसी है कि यहाँ

चाय, कॉफी, काजू, ड्रैगन फ्रूट, मसालों और सब्जियों की खेती के बड़े अवसर हैं। सरकार इस दिशा में तकनीक, प्रशिक्षण और अनुदान उपलब्ध करा रही है। जशपुर्योर ब्रांड की पहुंच अब देश-विदेश तक हो रही है। इसके अंतर्गत महुआ लड्डू, चिरौंजी एवं अन्य वन उत्पादों का प्रसंस्करण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जशपुर में अधोसंरचना के भी विभिन्न कार्य किया जा रहे हैं। यहां के युवाओं के तीरंदाजी सीखने की बहुत ललक है, इसके देखते हुए सत्रा पंडरापाठ में 20 करोड़ रुपए की लागत से आर्चरी अकादमी का निर्माण किया जा रहा है

साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए मेडिकल कॉलेज भी निर्माण किया जाएगा। इस अवसर पर विजय मंत्री श्री ओपी चौधरी ने मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों को रेखांकित किया। किसान महतारी सज्मेनल में किसान एवं महिलाओं को सज्मानित किया गया। इसके तहत कृषक समृद्धि योजना के तहत नलकूप खनन हेतु पोलीकार्प क्यूजर को 25

हजार रुपए, राजकिशोर और शिवप्रसाद साय को 18-18 हजार रुपए का अनुदान राशि का चेक प्रदान किया। इसी तरह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत शंकर लाल टोप्पो को 01 लाख 19 हजार 65 रुपए, इंद्रप्रताप को 01 लाख 31 हजार 455 रुपए एवं रंजीत को 01 लाख 12 हजार 955 रुपए का बीमा राशि का चेक और प्रमाण पत्र प्रदान किया। राष्ट्रीय खाद सुरक्षा एवं पोषण मिशन के तहत राजकुमार और लवकुश को सिंचाई पाईप हेतु 50 प्रतिशत अनुदान का प्रमाण पत्र वितरण किया। इसी प्रकार नारायणपुर की कमल स्व-सहायता समूह को 4 लाख रुपए बैंक लिंकेज, ग्राम मटासी के जीवन दीप स्व-सहायता समूह को 3 लाख रुपए एवं ग्राम रानीकोज्जो के संगम स्व-सहायता समूह को 1 लाख रुपए की बैंक लिंकेज राशि प्रदान किया गया। साथ हीसुभद्रा यादव वृन्दावती बाई, अंजू यादव एवं संगीता बाई को गाय पालन, कपड़ा दुकान एवं फास्ट फूड व्यवसाय में उल्लेखनीय योगदान के लिए सज्मानित किया गया।

रोड आगमन 09.28 बजे, प्रस्थान 09.30 बजे, गुंटकल आगमन 11.10 बजे, प्रस्थान 11.20 बजे, गुज्जी आगमन 11.53 बजे, प्रस्थान 11.55 बजे, अनंतपुर आगमन 12.53 बजे, प्रस्थान 12.55 बजे, धर्मवरम आगमन 13.55 बजे, प्रस्थान 14.00 बजे होते हुये 18.30 बजे यलहंका पहुंचेगी इसी प्रकार गाड़ी संख्या 08262 यलहंका(बेंगलुरु)-बिलासपुर शीतकालीन स्पेशल ट्रेन प्रत्येक बुधवार को यलहंका से 21.00 बजे रवाना होगी तथा दूसरे दिन गुरुवार को धर्मवरम आगमन 00.28 बजे, प्रस्थान 00.30 बजे, अनंतपुर आगमन 01.03 बजे, प्रस्थान 01.05 बजे, गुज्जी आगमन 02.03 बजे, प्रस्थान 02.05 बजे, गुंटकल आगमन 03.00 बजे, प्रस्थान 03.10 बजे, मंत्रालयम रोड आगमन 04.13 बजे, प्रस्थान 04.15 बजे, रायचूर आगमन 04.48 बजे, 04.50 बजे, कृष्णा जंज्शन आगमन 05.20 बजे , प्रस्थान 05.30 बजे, यादगीर आगमन 06.38 बजे, प्रस्थान 06.40 बजे, तांडूर आगमन 08.38 बजे, प्रस्थान 08.40 बजे, विकाराबाद आगमन 09.33 बजे, प्रस्थान 09.35 बजे, लिंगमपल्ली आगमन 10.30 बजे, प्रस्थान 10.32 बजे, सिकंदराबाद आगमन 11.10 बजे, प्रस्थान 11.20 बजे, चर्लपल्ली आगमन 11.43 बजे, प्रस्थान 11.45 बजे, काजीपेट आगमन 13.20 बजे, प्रस्थान 13.22 बजे, मंचिर्याल आगमन 15.10 बजे, प्रस्थान 15.12 बजे, सिरपुर कागजनगर आगमन 16.10 बजे, प्रस्थान 16.12 बजे, बल्लारशाह आगमन 19.30 बजे, प्रस्थान 19.40 बजे, चांदाफेर्ट आगमन 19.55 बजे, प्रस्थान 19.57 बजे, वडसा आगमन 21.38 बजे, प्रस्थान 21.40 बजे, गोंदिया आगमन 23.20 बजे, प्रस्थान 23.30 बजे, तीसरे दिन शुक्रवार को डोंगरगढ़ आगमन 00.28 बजे, प्रस्थान 00.30 बजे, राजनादागाँव आगमन 00.55 बजे, प्रस्थान 00.57 बजे, दुर्ग आगमन 01.40 बजे, प्रस्थान 01.45 बजे, रायपुर आगमन 02.25 बजे, प्रस्थान 02.30 बजे, भाटापारा आगमन 03.25 बजे, प्रस्थान 03.27 बजे होते हुये 04.30 बजे बिलासपुर पहुंचेगी इस शीतकालीन स्पेशल ट्रेन में 01 एसएलआरडी, 03 सामान्य, 04 स्लीपर, 02 एसी-३ इकोनामी, 08 एसी-३, 01 एसी -२ तथा जनरेटर कार सहित कुल 20 कोच की सुविधा उपलब्ध रहेगी

रेलवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 5 साल की अपहृत बच्ची बरामद, अगवा करने वाली आरोपी गिरफ्तार

रायपुर : जीआरपी रायपुर ने 5 वर्षीय अपहृत बच्ची को सुरक्षित बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी महिला को नादगा बीज (मध्यप्रदेश) से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल, 17 नवंबर 2025 को तड़के करीब 3 बजे एक दर्पणि अपनी 5 वर्षीय बच्ची के साथ रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर सो रहा था। इसी दौरान बच्ची अचानक लापता हो गई। परिजनों ने तुरंत जीआरपी रायपुर को इसकी सूचना दी, जिसके बाद शासनकीय रेल पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जीआरपी टीम ने स्टेशन परिसर के विभिन्न हिस्सों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज में एक संदिग्ध महिला बच्ची को लेकर स्टेशन से बाहर जाती दिखाई दी। इसके बाद पुलिस ने महिला की पहचान ज्योति देवी पति जसवीर सिंह, उम्र 40 वर्ष,

निवासी थाना नागदा बीज (म.प्र.) के रूप में की और उसके संभावित ठिकानों के बारे में जानकारी जुटाई। कई राज्यों में की गई तलाश संदिग्ध महिला का लोकेशन ट्रेस कर पुलिस टीम ने लगातार इंदौर, उज्जैन, नागदा सहित मध्य प्रदेश के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया। आखिरकार, 27 नवंबर की सुबह जीआरपी रायपुर को सफलता मिली और बच्ची को सुरक्षित बरामद करते हुए आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी महिला बच्ची को अपने साथ अलग-अलग स्थानों पर लेकर जाती रही। पुलिस ने तत्काल बच्ची को सुरक्षित परिजनों को सौंप दिया। इन धाराओं में केस दर्ज आरोपी के खिलाफ अपहरण से जुड़े गंभीर अपराधों—धारा 137(2) एवं 142 रेलवे अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।

आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता रही है। वर्ष 2025 में 50,762 क्विंटल बीज वितरित किया गया, जो पिछले 25 वर्षों की तुलना में 58 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार उर्वरकों का वितरण भी बढ़कर 89,632 मीट्रिक टन तक पहुंचा, जिसमें 45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। बीज उत्पादन के क्षेत्र में भी जिले ने उल्लेखनीय प्रगति की है। खरीफ में 76,764 क्विंटल और रबी में 9,026 क्विंटल बीज का उत्पादन किया गया, जो पूर्व तुलना में उल्लेखनीय बढ़ोतरी है। इन प्रयासों से किसानों को स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध होने लगे हैं, जिससे कृषि कार्यों की दक्षता और उत्पादन क्षमता में निरंतर सुधार हुआ है। वर्ष 2025 में कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं से कुल 1,06,659 कृषकों को लाभान्वित किया गया है, जो पिछले 25 वर्षों की तुलना में लगभग दस गुना अधिक है। यह उपलब्धि इस बात का संकेत है कि सरकारी सहायताएँ अब अधिक व्यापक और प्रभावी रूप से किसानों तक पहुँच रही हैं। प्रधानमंत्री किसान सज्मान निधि योजना के अंतर्गत जिले के 80,230 किसानों को 340.24 करोड़ रुपये की राशि सीधे आधार-सत्यापित बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है, जिससे योजना में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है।

जशपुरनगर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज कुनकुरी विकास खंड के ग्राम नारायणपुर में कुज्हार समाज के द्वारा आयोजित श्री विष्णु महायज्ञ, चक्र पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए और पूजा अर्चना कर प्रदेश के सुख समृद्धि खुशहाली की कामना की।

उन्होंने कुज्हारों को इलेक्ट्रॉनिक चाक का वितरण किया। इस अवसर पर विजय मंत्री ओ पी चौधरी, विधायक श्रीमती गोमती साय और रायमुनी भगत, पद्म जागेश्वर यादव, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष शंजभू राम चक्रवर्ती,जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, नगर पालिका अध्यक्ष जशपुर अरविंद भगत, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, नगर पालिका

सज्जोधित में सबसे पहले संसार के रचयिता और पालनहार भगवान विष्णु को प्रणाम किए और पूरे छत्तीसगढ़वासियों के सुख, समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि आज पावन ग्राम नारायणपुर में कुज्हार समाज द्वारा आयोजित विष्णु महायज्ञ का यह पवित्र अवसर हमारी सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उदाहरण है। इस महायज्ञ में चक्र पूजा का आयोजन विशेष रूप से प्रेरणादायक है, जो हमारे कुज्हार समाज की गहन परंपराओं को दर्शाता है। मैं इस आयोजन में पहले भी आपके बीच आता रहा हूँ। जब भी इस कार्यक्रम में आता हूँ, मुझे नयी ऊर्जा मिलती है।

चक्र पूजा न केवल मिट्टी के चक्र की आराधना है, बल्कि यह सृष्टि के निर्माण, मेहनत और रचनात्मकता का

प्रतीक है। विष्णु महायज्ञ जैसे आयोजनों में आपकी भूमिका हमें याद दिलाती है कि कुज्हार समाज प्रजापति की संतान के रूप में सृष्टि रचना में योगदान देता है और आज का यह कार्यक्रम उसकी जीवंत अभिव्यक्ति है।

विगत 25 वर्षों में दुर्ग जिले के कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति

रायपुर : दुर्ग जिले के कृषि विभाग ने विगत 25 वर्षों में कृषि विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियाँ दर्ज की हैं, जिनका सकारात्मक असर जिले की कृषि अर्थव्यवस्था और किसानों के जीवन स्तर पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। वर्ष 2025 के दौरान खरीफ और रबी फसलों के क्षेत्र एवं उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। खरीफ फसल का क्षेत्राच्छादन 1,46,276 हेक्टेयर तक पहुँच गया है, जो पिछले 25 वर्षों की तुलना में 4 प्रतिशत अधिक है, वहीं रबी फसल का क्षेत्र 53,660 हेक्टेयर रहा, जिसमें 8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। उत्पादन के स्तर पर भी जिले का प्रदर्शन ऐतिहासिक रहा है। खरीफ फसल का कुल उत्पादन 7.20 लाख मीट्रिक टन रहा, जो 53 प्रतिशत अधिक है, जबकि रबी उत्पादन 84 हजार मीट्रिक टन तक पहुँच गया, जो 43 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है। उत्पादकता में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है—खरीफकी उत्पादकता 4922 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और रबी की उत्पादकता 1565 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रही, जो क्रमशः 48 और 34 प्रतिशत अधिक है। फसल सघनता भी बढ़कर 133 प्रतिशत हो गई है, जो 25 वर्षों की तुलना में 9 प्रतिशत की वृद्धि है। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले कृषि

आदानों की उपलब्धता सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता रही है। वर्ष 2025 में 50,762 क्विंटल बीज वितरित किया गया, जो पिछले 25 वर्षों की तुलना में 58 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार उर्वरकों का वितरण भी बढ़कर 89,632 मीट्रिक टन तक पहुंचा, जिसमें 45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। बीज उत्पादन के क्षेत्र में भी जिले ने उल्लेखनीय प्रगति की है। खरीफ में 76,764 क्विंटल और रबी में 9,026 क्विंटल बीज का उत्पादन किया गया, जो पूर्व तुलना में उल्लेखनीय बढ़ोतरी है। इन प्रयासों से किसानों को स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध होने लगे हैं, जिससे कृषि कार्यों की दक्षता और उत्पादन क्षमता में निरंतर सुधार हुआ है। वर्ष 2025 में कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं से कुल 1,06,659 कृषकों को लाभान्वित किया गया है, जो पिछले 25 वर्षों की तुलना में लगभग दस गुना अधिक है। यह उपलब्धि इस बात का संकेत है कि सरकारी सहायताएँ अब अधिक व्यापक और प्रभावी रूप से किसानों तक पहुँच रही हैं। प्रधानमंत्री किसान सज्मान निधि योजना के अंतर्गत जिले के 80,230 किसानों को 340.24 करोड़ रुपये की राशि सीधे आधार-सत्यापित बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है, जिससे योजना में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है।

जशपुरनगर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज कुनकुरी विकास खंड के ग्राम नारायणपुर में कुज्हार समाज के द्वारा आयोजित श्री विष्णु महायज्ञ, चक्र पूजा कार्यक्रम में शामिल हुए और पूजा अर्चना कर प्रदेश के सुख समृद्धि खुशहाली की कामना की।

उन्होंने कुज्हारों को इलेक्ट्रॉनिक चाक का वितरण किया। इस अवसर पर विजय मंत्री ओ पी चौधरी, विधायक श्रीमती गोमती साय और रायमुनी भगत, पद्म जागेश्वर यादव, माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष शंजभू राम चक्रवर्ती,जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, नगर पालिका अध्यक्ष जशपुर अरविंद भगत, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, नगर पालिका

जशपुर उपाध्यक्ष यश प्रताप सिंह जूदेव, कृष्ण कुमार राय, विजय आदित्य प्रताप सिंह जूदेव, जिला पंचायत सदस्य अनिता सिंह, दुलारी सिंह एवं मलिता बाई , जनपद पंचायत अध्यक्ष दुलदुला राजकुमार सिंह, सुनील गुप्ता, मुकेश शर्मा, मनीष अग्रवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशिमोहन सिंह, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक कुमार सहित जनप्रतिनिधिगण और अधिकारीगण मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने ग्राम गोरिया में माटी कला बोर्ड के माध्यम से कुज्हारों के लिए ग्लेजिंग यूनिट स्थापित करने घोषणा की और कुज्हार समाज के मंगल भवन विस्तार के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा की है। उन्होंने माँ रतनेश्वरी की जय रूद्रपाल देव की जय कर सभी को नमस्कार और जय जोहार करते हुए अपने

सज्जोधित में सबसे पहले संसार के रचयिता और पालनहार भगवान विष्णु को प्रणाम किए और पूरे छत्तीसगढ़वासियों के सुख, समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि आज पावन ग्राम नारायणपुर में कुज्हार समाज द्वारा आयोजित विष्णु महायज्ञ का यह पवित्र अवसर हमारी सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उदाहरण है। इस महायज्ञ में चक्र पूजा का आयोजन विशेष रूप से प्रेरणादायक है, जो हमारे कुज्हार समाज की गहन परंपराओं को दर्शाता है। मैं इस आयोजन में पहले भी आपके बीच आता रहा हूँ। जब भी इस कार्यक्रम में आता हूँ, मुझे नयी ऊर्जा मिलती है।

चक्र पूजा न केवल मिट्टी के चक्र की आराधना है, बल्कि यह सृष्टि के निर्माण, मेहनत और रचनात्मकता का

प्रतीक है। विष्णु महायज्ञ जैसे आयोजनों में आपकी भूमिका हमें याद दिलाती है कि कुज्हार समाज प्रजापति की संतान के रूप में सृष्टि रचना में योगदान देता है और आज का यह कार्यक्रम उसकी जीवंत अभिव्यक्ति है।



भुवनेश्वर में सबसे ज्यादा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, ढाई साल में १३८४४ चालान

भुवनेश्वर २६/०९ (संवाददाता): ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। पिछले ढाई वर्षों के दौरान राजधानी में यातायात नियम तोड़ने पर कुल 13,844 चालान काटे गए, जबकि विभिन्न मामलों में 144 वाहनों को जप्त किया गया। ओडिशा के परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना ने विधानसभा में यह जानकारी दी। परिवहन मंत्री ने विधायक प्रताप केशरी देब के एक सवाल के जवाब में राज्य में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन और उसके खिलाफ की गई कार्रवाई से जुड़े आंकड़े सदन के सामने रखे। उन्होंने बताया कि भुवनेश्वर में इस अवधि के दौरान सबसे अधिक चालान की कार्रवाई की गई है। राजधानी में बढ़ते यातायात के बीच नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की गई। मंत्री की ओर से विधानसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक, पिछले ढाई वर्षों में भुवनेश्वर में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामलों में 13,844 चालान जारी किए गए। इसके अलावा 144 वाहनों को जप्त किया



गया। इन आंकड़ों के आधार पर चालान की संख्या के मामले में भुवनेश्वर राज्य में सबसे आगे रहा। वहीं कटक जिला ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जारी चालान की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर रहा। कटक में पिछले ढाई वर्षों के दौरान 10,844 चालान काटे गए। यहां नियमों के उल्लंघन के अलग-अलग मामलों में कुल 291 वाहनों को जप्त किया गया। भुवनेश्वर की तुलना में कटक में चालान की संख्या कम रही, लेकिन जप्त किए गए वाहनों की संख्या अधिक दर्ज की गई।

राज्य स्तर के आंकड़ों की बात करें तो पिछले ढाई वर्षों में ओडिशा में बड़ी संख्या में लोगों के खिलाफ यातायात नियमों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई हुई है। परिवहन मंत्री के अनुसार, इस अवधि के दौरान पूरे राज्य में 4,15,159 लोगों द्वारा ट्रैफिक

नियमों का उल्लंघन दर्ज किया गया। इन मामलों में अधिकारियों ने नियमानुसार कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया। यातायात नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामलों में पिछले ढाई वर्षों में राज्यभर से कुल 15.16 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया है। यह राशि विभिन्न प्रकार के यातायात उल्लंघनों के मामलों में की गई कार्रवाई के तहत वसूली गई। इसी अवधि में पूरे ओडिशा में कुल 1,812 वाहनों को जप्त किया गया। राज्य में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामलों की व्यापक तस्वीर पेश करते हैं। चार लाख से अधिक लोगों पर कार्रवाई से स्पष्ट होता है कि यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए संबंधित विभाग और अधिकारी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। विशेष रूप से भुवनेश्वर और कटक जैसे

बड़े शहरी क्षेत्रों में वाहनों की संख्या और यातायात का दबाव अधिक होने के कारण ट्रैफिक प्रबंधन महत्वपूर्ण विषय बना हुआ है। भुवनेश्वर राज्य की राजधानी होने के साथ प्रमुख प्रशासनिक और व्यावसायिक केंद्र भी है। शहर में रोजाना बड़ी संख्या में वाहनों की आवाजाही होती है। ऐसे में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन न केवल यातायात व्यवस्था को प्रभावित करता है, बल्कि सड़क सुरक्षा से जुड़े जोखिम भी बढ़ा सकता है। इसी कारण नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। कटक में भी यातायात व्यवस्था बड़ी चुनौती बनी हुई है। शहर के कई इलाकों में व्यस्त सड़कों और वाहनों की अधिक आवाजाही के कारण ट्रैफिक नियमों का पालन महत्वपूर्ण है। पिछले ढाई वर्षों में 10,844 चालान और 291 वाहनों की जप्ती के आंकड़े बताते हैं कि वहां भी बड़े पैमाने पर प्रवर्तन कार्रवाई की गई है। परिवहन मंत्री की ओर से पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, पूरे राज्य में 4.15 लाख से अधिक लोगों के खिलाफ ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के मामले दर्ज किए गए। इस

दौरान 15 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला जाना भी कार्रवाई के व्यापक स्तर को दर्शाता है। वहीं 1,812 वाहनों की जप्ती से पता चलता है कि कई मामलों में अधिकारियों ने केवल जुर्माना लगाने तक कार्रवाई सीमित नहीं रखी। यातायात नियमों का पालन सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और सुरक्षित परिवहन व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है। वाहन चालाते समय निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने से चालक के साथ-साथ सड़क पर मौजूद अन्य लोगों की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में परिवहन और यातायात विभाग की ओर से नियमों के पालन पर लगातार जोर दिया जाता है। फिलहाल विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों ने भुवनेश्वर और कटक में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की स्थिति को सामने रखा है। भुवनेश्वर 13,844 चालान के साथ सबसे ऊपर रहा, जबकि कटक में 10,844 चालान काटे गए। राज्यभर में 4,15,159 उल्लंघनकर्ताओं से जुड़े मामलों में कार्रवाई, 1,812 वाहनों की जप्ती और 15.16 करोड़ रुपये के जुर्माने की वसूली पिछले ढाई वर्षों के दौरान की गई है।

सुंदरगढ़ में गजराज का आतंक

राउरकेला २६/०९ (संवाददाता): सुंदरगढ़ जिले के लाठीकट तथा सबडेगा ज़िलों में 81 हाथियों के झुंड ने आतंक मचा रखा है। हाथियों के द्वारा फसल को नुकसान पहुंचाने से किसानों की नौद हराग हो गई है। वन विभाग की ओर से इन्हें खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। लाठीकट ज़िलों में 41 हाथियों के होने से बुचा हांडाए डाइटोलाए रेलापोपए बिरुआल क्षेत्र के लोग हाथियों से आतंकित हैं। सबडेगा ज़िलों में 40 हाथियों का झुंड है।

ओडिशा पुलिस ने सरकार से 76 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की

भुवनेश्वर २६/०९ (संवाददाता): पुलिस स्टेशनों और चौकियों में लगे सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े हैं, ऐसे में ओडिशा पुलिस ने उनकी बहाली और रखरखाव के लिए सरकार से 76 करोड़ रुपये जारी करने की मांग की है। यह राशि सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के लिए निर्धारित की गई थी लेकिन वित्तीय वर्ष 2025-26 में इसे सरेंडर कर दिया गया था। गृह विभाग को लिखे एक पत्र में, अतिरिक्त मुख्य सचिव, एडीजी (कानून और व्यवस्था) संजय कुमार ने इस मामले पर विचार-विमर्श करने और सीसीटीवी प्रणाली की स्थापना और रखरखाव के लिए ओडिशा कंप्यूटर एप्लीकेशन सेंटर (ओसीएसी) को आगे के भुगतान के लिए अनुपूरक

बजट के तहत ४76 करोड़ की धनराशि जारी करने पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक का अनुरोध किया। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य भर में 645 पुलिस स्टेशनों और 263 पुलिस चौकियों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।

इस साल मार्च की शुरुआत में पुलिस और गृह विभाग के अधिकारियों की एक बैठक के दौरान ओसीएसी से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया था कि राज्य के सभी पुलिस स्टेशनों और चौकियों में लगे सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह चालू रहें। हालाँकि, 17 सितंबर तक पुलिस स्टेशनों में 795 और चौकियों में 33 सीसीटीवी कैमरे ऑफलाइन पाए गए।

सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार, सीसीटीवी कैमरों को चौबीसों घंटे पूरी तरह कार्यात्मक स्थिति में बनाए रखना आवश्यक है। कुमार ने अतिरिक्त मुख्य सचिव से राज्य के पुलिस स्टेशनों और चौकियों में स्थापित सभी गैर-कार्यात्मक सीसीटीवी कैमरों की तत्काल बहाली के लिए ओसीएसी को आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह किया। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने भी पहले राज्य सरकार को सभी पुलिस स्टेशनों और चौकियों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया था। यह निर्देश सितंबर 2024 में यहां भरतपुर पुलिस स्टेशन में एक सेना अधिकारी और उसकी मंगेतर की कथित हिरासत में यातना के बाद जारी किया गया था।

छात्रा की संदिग्ध मौत मामले में चेन्नई से प्रेमी गिरफ्तार, आमने-सामने होगी पूछताछ करेगी पुलिस

भुवनेश्वर २६/०९ (संवाददाता): केंद्रापड़ा जिले के पट्टामुंडई क्षेत्र की एक अंतिम वर्ष की स्नातक छात्रा की रहस्यमय मौत के मामले में पुलिस ने अहम कार्रवाई करते हुए मृतका के प्रेमी को चेन्नई से हिरासत में लिया है। युवक

से जल्द ही पूछताछ की जाएगी, जिससे मामले की गुत्थी सुलझाने में मदद मिलने की उम्मीद है। गत सप्ताह छात्रा अपने घर में आग से बुरी तरह झुलसी हुई हालत में मिली थी। यह घटना संदिग्ध परिस्थितियों में घटी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों और मृतका के परिवार ने इस मौत को आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए इसमें साजिश की आशंका जताई थी। पीड़ित छात्रा के परिजनों ने थाने में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया था कि उसका प्रेमी उसे मानसिक रूप से

प्रताड़ित करता था और जलैकमेल कर रहा था। मृतका के पिता ने यहां तक कहा कि युवक की ओर से लगातार धमकी और मानसिक दबाव के चलते उनकी बेटी ने यह कठोर कदम उठाया होगा। शिकायत के बाद आरोपी फरार हो गया था, लेकिन केंद्रापड़ा पुलिस की विशेष टीम ने तकनीकी निगरानी और सूचना के आधार पर उसे चेन्नई से पकड़ने में सफलता पाई। आरोपी को पूछताछ के लिए केंद्रापड़ा लाया गया है, जहां उससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी।

दस्तावेज से बनाते थे फर्जी सिम कार्ड, साइबर क्राइम में इस्तेमाल का शक, तीन गिरफ्तार

भुवनेश्वर २६/०९ (संवाददाता): ओडिशा पुलिस ने गुरुवार को ग्राहकों के पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल करके फर्जी सिम कार्ड बनाने और बेचने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। संबलपुर जिला पुलिस ने जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनकी पहचान सूरज बाग (24), मालती ओराम उर्फ माला (29) और पापू उर्फ शेख परवेज (32) के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि उन्होंने 22 सितंबर, 2026 को संबलपुर साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज केस नंबर 34/26 की जांच के दौरान इस रैकेट का पता लगाया। आरोप



है कि ये लोग ग्राहकों के पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल करके एक ही नंबर पर कई सिम कार्ड बनाते थे। एक सिम तो ग्राहक को दे दिया जाता था, जबकि बाकी सिम अपने पास रखकर दूसरों को बेच दिए जाते थे। जांच में पता चला कि इनमें से कुछ सिम कार्ड का इस्तेमाल झारखंड के जामताड़ा में साइबर अपराधों के लिए किया जा रहा

था। पुलिस को यह भी पता चला कि रैकेट से हुई कमाई को इसमें शामिल लोगों के बीच बांट लिया जाता था। जप्त की गई चीजों में चार मोबाइल फोन, चार एंजिटव सिम कार्ड, 120 सीलबंद खाली एयरटेल सिम कार्ड, तीन बैंक पासबुक, एक चेक बुक, एक आधार कार्ड, एक फोनपे ज्यूआर कोड स्कैनर, चार हलफनामे, घर किराए पर

लेने का एग्रीमेंट, 10 एयरटेल पैजफलेट और चार एयरटेल 5जी प्लस साइनबोर्ड शामिल हैं। पुलिस इस मामले में शामिल अन्य लोगों, बनाए और सप्लाई किए गए सिम कार्ड की संख्या, सिम कार्ड लेने वालों और इसमें शामिल पैसों के बारे में पता लगाने के लिए जांच कर रही है। पुलिस जामताड़ा से कथित संबंधों की भी जांच कर रहे हैं, जो जांच का एक मुख्य केंद्र बनकर उभरा है। अधिकारियों ने बताया कि फर्जी और धोखाधड़ी से हासिल किए गए सिम कार्ड उन मुख्य साधनों में से हैं जिनका इस्तेमाल साइबर अपराधी धोखाधड़ी करने के लिए करते हैं।

आरएसपी में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के जीवनसाथियों के लिए 'रोशनी सक्षम साथी' परामर्श कार्यशाला आयोजित

राउरकेला २६/०९ (संवाददाता): राउरकेला इस्पात संयंत्र में अक्टूबर-दिसंबर 2026 के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के जीवनसाथियों के लिए 'रोशनी-सक्षम साथी' परामर्श कार्यशाला का आयोजन 19 सितंबर, 2026 को सिविक सेंटर में किया गया। इस अवसर पर मुख्य महा प्रबंधक प्रभारी (सेवाएँ), श्री ए.सी.सरकार मुख्य अतिथि तथा महा प्रबंधक प्रभारी (मानव संसाधन), श्री एस.मेहरोत्रा सज्जमानित अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर संबोधित करते हुए श्री सरकार ने जीवनसाथियों से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सहयोग एवं सहानुभूति प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के



बाद जीवन में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने में जीवनसाथियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है तथा उनका सहयोग इस संक्रमणकाल को सहज एवं सकारात्मक बनाने में सहायक होगा। कार्यशाला के दौरान सेवानिवृत्ति के रूप में जीवन के महत्वपूर्ण बदलाव काल का सकारात्मक रूप से सामना करने तथा उद्देश्यपूर्ण एवं सक्रिय

जीवन जीने के लिए सहायक महाप्रबंधक (सीपी-2), श्री बाबुला नाहक ने सकारात्मक सोच विकसित करने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। जबकी सहायक महा प्रबंधक (विज्ञ एवं लेखा), श्री पप्पू कुमार ने वित्तीय सुरक्षा की योजना से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। उप महा प्रबंधक (उद्यानकृषि), श्री टी.बी.टोप्पो, ने सेवानिवृत्ति के बाद सक्रिय

एवं सार्थक जीवन के लिए विभिन्न गतिविधियों से जुड़े उपयोगी सुझाव साझा किए। अतिरिक्त सी.एम.ओ. (ओ.एच.एस.सी.), डॉ. एस.कुमार ने 'अर्थपूर्ण जीवन के लिए उच्चम स्वास्थ्य, कल्याण एवं समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करना' विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। सहायक प्रबंधक (एच.आर.), श्री एस.पी.माझी ने उपस्थित कर्मिसमूह का स्वागत किया तथा औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित भी किया। कार्यशाला का संचालन उप प्रबंधक (एच.आर.), श्री एस.सी. नायक ने सहायक महा प्रबंधक (एच.आर.), श्री अविनाश के मार्गदर्शन में तथा एच.आर.-ई.आर. एंड सी. टीम के सहयोग से किया।



भारतीय थल सेना

JOIN INDIAN ARMY AS AN OFFICER

www.joinindianarmy.nic.in



अधिकारी प्रविष्टि

तकनीकी स्नातक कोर्स (टी जी सी-145) (जुलाई 2027 में निर्धारित) के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

आवेदन 30 सितम्बर 2026 से 29 अक्टूबर 2026 तक खुले रहेंगे।

OFFICER ENTRY

Online applications are invited for Technical Graduate Course (TGC-145) (scheduled in July 2027).

Applications will remain open from 30 Sep 2026 to 29 Oct 2026.



नोट :

- सेना में भर्ती पूर्णतया पारदर्शी और मुफ्त है। दलालों से सावधान रहें।
- विस्तृत नोटिफिकेशन के लिये कृपया www.joinindianarmy.nic.in पर जाएं।

Note:

- Recruitment in the Army is totally transparent and free. Beware of touts.
- For detailed Notification, please visit www.joinindianarmy.nic.in

CBC10601/11/0030/2627